सूविचार

मित्रता आनंद को दोगुना और दुख को आधा कर देती है।

दैनिक

इंटरनल न्यूज

सच की तह तक....

internalnews@gmail.com

www.internalnews.com

वर्ष : 11 | अंक : 314 | पृष्ठ : 08 | मूल्य 1 रूपये | भोपाल, शनिवार 07 फरवरी 2026 | RNI NO. MPHIN/2015/61965

संक्षिप्त समाचार

सड़क हादसों में कांग्रेस नेता समेत 8 मौतें

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग चार सडक़ हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हैं। पहली घटना कोरबा की है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और ऑटोमोबाइल एजेंसी मालिक की मौत हो गई, जबकि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष समेत दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी घटना रायपुर की है। सीएम हाउस के पास तेज रफ्तार सरकारी वाहन ने स्कूल जा रहे ईयू स्कूटर सवार भाई-बहन को टक्क र मार दी। हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। तीसरी घटना बिलासपुर की है, जहां पिकअप की टक्क र से बाइक सवार पति-प ी और उनकी बेटी की मौत हो गई। तीनों बेलपान मेला देखकर लौट रहे थे। ग्राम तेंदुआ मोड़ के पास सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्क र मार दी। वहीं चौथी घटना कांकेर की है। जन्मदिन मनाने के लिए कार से माकड़ी ढाबा जा रहे दो नाबालिगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सडक़ किनारे अनियंत्रित होकर पलटते हुए पेड़ से टकरा गई। कार में छह दोस्त सवार थे, जिनमें से चार घायलों का इलाज जारी है।

फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर एफआईआर

लखनऊ। यूपी में मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' के नाम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत सीएम के निर्देश पर खुद हजरतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कराई है। पुलिस का कहना है कि फिल्म का नाम और इसकी कहानी एक खास जाति और समुदाय, खासकर ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाती है। इससे लोगों में नाराजगी फैल सकती है। कानून-व्यवस्था बिगडऩे का खतरा है। इधर, मायावती ने इसे ब्राह्मणों का अपमान बताया। केंद्र सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की। इससे पहले, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कहा- फिल्म का टाइटल समाज को 'घूसखोर' दिखा रहा है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। प्रयागराज के संतों ने भी फिल्म को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि बॉलीवुड का रवैया दोहरा है। एक खास वर्ग को बार-बार टारगेट कर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, जिससे समाज को बांटने का काम होता है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, कहा- गोवंश यदि सुरक्षित हैं इसका हो परीक्षण

वाराणसी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोवंश को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में राज्य के पशुपालन मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए गोकशी के गंभीर मुद्दे को 'भ्रम' और 'असत्य' करार दिया। मंत्री ने दावा किया था कि राज्य में गो-वंश पूर्णतः सुरक्षित है। शंकराचार्य ने पत्र में कहा कि धर्मसत्ता और राजसत्ता के बीच सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दावों का धरातलीय एवं वैज्ञानिक परीक्षण हो। यदि शासन का विश्वास अडिग है कि राज्य में गोहत्या पूर्णतः बंद हो चुकी है, तो पारदर्शिता के लिए ज्योतिषपीठ के प्रतिनिधियों को कुछ बिंदुओं पर अनुमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होने मांग की कि निर्यातित मांस का डीएनए परीक्षण कराया जाए। हापुड़, अलीगढ़, मेरठ और उन्नाव जैसे निर्यात केंद्रों से रैंडम सैंपलिंग कर स्वतंत्र जांच की अनुमति दी जाए। चर्म शोधन इकाइयों का निरीक्षण किया जाए। कानपुर एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली खालों के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए। परिवहन एवं सीमा निरीक्षण किया जाए। अंतर्राज्यीय सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों के आकस्मिक निरीक्षण में प्रशासनिक सहयोग दिया जाए। नगर निकायों एवं निजी वधशालाओं की व्यवस्था की धरातलीय जांच के लिए 'सरप्राइज ऑडिट' का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा गौशाला एवं निस्तारण केंद्रों का ऑडिटरू सरकारी गौशालाओं में मृत्यु के कारणों एवं शवों के निस्तारण की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए और अधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची जारी की जाए।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा

राज्य सरकार किसान, उद्योग और व्यापार को साथ लेकर तैयार कर रही है विकास का नया मॉडल : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का फूड बॉस्केट बन चुका है। मध्यप्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और दाल उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार किसान, उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है।

राज्य सरकार जमीन हो या मशीन हर स्तर पर किसानों और व्यापारियों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने तुअर से मंडी टैक्स हटाया है, इससे दाल मिल उद्योग को लाभ मिलेगा। उड़द और मसूर पर भी राहत देने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में दालों का विशेष महत्व है। मूंग और मसूर की दालों पर मुहावरे बन गए। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। यह गर्व का विषय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी संस्कृति में दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्त्रोत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इन्दौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोशिएशन के ग्रेन-एक्स इंडिया प्रदर्शनी अंतर्गत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में दूध और दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में मसूर और उड़द उत्पादन को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही बोनस देने की योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों सहित उद्यमियों को भी लाभ होगा, इंदौर में उद्योग-व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मध्यप्रदेश देश के मध्य में है, यहां से रोड, रेल और हवाई हर तरह की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। प्रदेश में एयरकार्गो के विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं, जिससे व्यापार व्यावसाय विस्तार को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दाल मिल से संबंधित उद्यमियों, मशीन निर्माताओं, निर्यातकों, व्यापारियों, कृषकों, आदि के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की कार्यशाला शीघ्र ही भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की एक विशिष्ट छवि बनी है। भारत के बजट के आधार पर दुनिया अपनी नीतियां तय करती है। अब समय बदल चुका है। भारत सरकार पर किसी टैरिफ का असर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए अन्नदाता किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हितों के साथ सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 श्रेणियों- गरीब, अन्नदाता (किसान), युवा और नारी में देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का लक्ष्य रखा है।

जब विश्वास डगमगाया, तब देव धनी सरकार बने संबल

चौथ मेले में श्री रुद्र आदित्यराज राला साहब के सान्निध्य में पीड़ा से मिला समाधान

देवधानी सरकार धाम। चतुर्थी मेले के पावन अवसर पर देव धनी सरकार मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि टूटे मनों के लिए आश्रय बन गया। देव धनी सरकार की असीम कृपा से पूज्य श्री रुद्र आदित्यराज राला साहब के सान्निध्य में ऐसा दृश्य साकार हुआ, जहाँ पीड़ा लेकर आए श्रद्धालु आशा और विश्वास के साथ लौटते दिखाई दिए।

न कश्चिद् दु:खितो भवेत

(कोई भी मनुष्य दु:खी न रहे—यही धर्म का सार है)

स्वास्थ्य, रोज़गार, पारिवारिक तनाव, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति से जूझते श्रद्धालु जब देवधानी सरकार धाम पहुँचे, तो उन्हें केवल आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि सुनवाई, मार्गदर्शन और समाधान का अनुभव हुआ। पूज्य राला साहब के आशीर्वचन ने निराश हृदयों में फिर से जीवन की लौ जला दी। महाआरती के समय मंदिर परिसर भावनाओं से भर उठा—हाथ जुड़े, आँखें नम हुईं और अंत:करण श्रद्धा से भर गया।

श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्

(श्रद्धा रखने वाला ही सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है)

एवीएन सत्संग और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु की गई व्यवस्थाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यह मेला केवल पूजा नहीं, बल्कि मानव सेवा का जीवंत यज्ञ है।

सेवा परमो धर्म:

(सेवा ही सर्वोच्च धर्म है)

देव धनी सरकार धाम में संपन्न यह चौथ मेला उन अनगिनत लोगों के लिए यादगार बन गया, जिन्होंने निराशा के बीच ईश्वर को अपने सबसे निकट महसूस किया।

देव धनी सरकार मंदिर में श्री रुद्र आदित्यराज राला साहब के सान्निध्य में चौथ मेले के दौरान श्रद्धा, अश्रु और समाधान–आस्था का जीवंत दृश्य।

सुप्रीम कोर्ट की प्रशांत किशोर को फटकार

जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे

पटना। प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की और मांग को खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। कोर्ट ने जनसुराज पार्टी को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया तो कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका

वापस ले ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पार्टी चुनाव में अपना सब कुछ हार गई तब वो यहां आ गई। आपको सद्भावना के बारे में भी बताना होगा। उन्होंने कहा कि फ्रीबीज (मुफ्त योजनाओं) के मुद्दे की हम जांच कर रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा मामला है, जहां एक पॉलिटिक्ल पार्टी, जो चुनाव में सब कुछ हार गई, हमारे सामने आ गई है। हम राजनीतिक दलों के कहने पर फ्रीबीज के मुद्दे की जांच नहीं करना चाहते हैं। सीजेआई ने साफ कहा कि कोई चाहे तो योजना को चुनौती दे सकता है, लेकिन यहां मुख्य मांग चुनाव को रद्द करने की है। जनसुराज के वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा कि जो राज्य गरीब हैं और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, ना ही पॉलिसी मैटर था लेकिन वहां सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, तो महिलाओं के खाते में दस दस हजार रुपए डाले. ये चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है।

पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ 3 नक्सली मारे गए, 1 जवान शहीद

गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के सी-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इसमें 3 नक्सली मारे गए हैं और 1 जवान शहीद हुआ है। अब तक महिला समेत तीन माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही एक एके-47 और एक एसएलआर भी जब्त की गई है। हालांकि, अब तक तीनों माओवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गढ़चिरौली के घने जंगलों में नक्सलियों का एक बड़ा कैंप सक्रिय होने की सूचना मिली थी।

नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा हादसा

बरातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत

पिथौरागढ़। भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैतडी में बैतडी से बजांग जा रही बरात की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 13 बरातियों की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरुवार की रात्रि बैतडी के पुरचुंणी नगरपालिका सात भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग के सुनकुडा जा रही बस पुरचूंणी के बड़गांव मोड से अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरिक्षक बलदेव बडू ने बताया कि रात्रि के समय नेपाल एपीएफ, प्रहरी एवं स्थानीय जनता द्वारा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया।

दुर्घटना में मरने वालों में बजांग बित्थड चीर गांव पालिका निवासी केशव राज जोशी (40) अशोक राज जोशी 13, बसंत राज जोशी (35), बिष्णु दत्त जोशी (41), नरेश राज जोशी (42), बिशन दत्त जोशी (17) दीपक जोशी (28), किशन जोशी (46), बजांग केदारस्यु गांव पालिका निवासी मोहन देव भट्ट (60) केशव भट्ट (27), बजांग जय पृथ्वी नगरपालिका निवासी बसंत राज रतला (40), बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका निवासी पुष्पा अवस्थी (40), बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका निवासी सुशील जोशी शामिल हैं। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरिक्षक बलदेव बडू ने बताया कि बस दुर्घटना में छह बरातियों की घटना स्थल में ही मौत हो गई। पांच बरातियों की डडेलधुरा अस्पताल में और दो बरातियों की कोटिला अस्पताल में मौत हो गई। घायलों में कुछ और बरातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

संसद

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का जोरदार हमला

लोकसभा में लगातार पांचवे दिन भी जारी रहा हंगामा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा शुक्रवार को लगातार पांचवे दिन भी जारी रहा जिसके कारण सदन नहीं चला और लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे जब पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक हुई, तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी और द्रविड़ मुनेत्र कडग़म -डीएमके के विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीचोबीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे।

पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया। विपक्ष के हंगामे के बीच, मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के कागजात रखे। अध्यक्ष द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद, विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सदन के कामकाज में सूचीबद्ध थी, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध के कारण इसे नहीं लिया जा सका।

जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी और सदन में व्यवधान करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। ओम बिरला ने कहा, उन्होंने प्रश्नकाल की शुरुआत के समय कहा, मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राजपाल जी और प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्यों के प्रश्न हैं। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हो चुका है। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चा और संवाद हो। लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं। देश की जनता ने पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको संसद में नहीं भेजा है। आपको चर्चा के लिए भेजा गया है। आप नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। ऐसा सदन मैं नहीं चला सकता।

शुरू होते ही सदन स्थगित : पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी और हंगामा में करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस दौरान उन्होंने हंगामे के बीच ही जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। हंगामा कर रहे सदस्यों से उन्होंने अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया और कहा कि हंगामे के बीच वह सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते है इसलिए सभी सदस्य शांत होकर अपनी सीटों पर बैठ जाए। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा तेज होता गया जिसकी कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों में भारी हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन हंगामा तेज होता गया जिसके कारण उन्हें सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

नर्मदा को ड्रेनेज से मुक्त करे सरकार, समर्थन मूल्य 3000 रुपए करे घोषितः रीना बोरासी

» मतदाता सूची पुनरीक्षण पर उठाए सवाल, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं खोलने पर भाजपा सरकार को घेरा » महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध खनन, मनरेगा और किसानों के मुद्दे प्रमुख

इटारसी। मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने नर्मदापुरम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नर्मदा नदी में मिल रहे ड्रेनेज और औद्योगिक अपशिष्ट को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पवित्र जीवनदायिनी नर्मदा आज प्रदूषण की मार झेल रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

रीना बोरासी ने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि प्रदेश की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। बावजूद इसके नर्मदा के जल को स्वच्छ रखने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं बनाई गई। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार समग्र कार्ययोजना बनाकर नर्मदा नदी को ड्रेनेज और उद्योगों के केमिकल वेस्ट से पूर्णतः मुक्त करे।

उन्होंने आरोप लगाया कि नर्मदा किनारे अवैध खनन ने नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। करोड़ों पौधे लगाने के नाम पर खर्च की गई राशि को उन्होंने भ्रष्टाचार बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नर्मदा तट पर किसी भी प्रकार के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल : महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है। नर्मदापुरम में लगभग 1.75 लाख नागरिकों को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। वर्षों से एक ही स्थान पर रहकर मतदान कर रहे मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

नर्मदापुरम की उपेक्षा का आरोप : रीना बोरासी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन नर्मदापुरम को अब तक मेडिकल कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालय जैसी मूलभूत सौगात नहीं मिल सकी। छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, परंतु नर्मदापुरम की लगातार उपेक्षा की जा रही है।

गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए करने की मांग : किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित 2585 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। बढ़ती लागत, खाद-बीज और डीजल के दामों को देखते हुए किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके।

मनरेगा के प्रावधानों में बदलाव पर आपत्ति : उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था। यदि रोजगार नहीं मिलता था तो सरकार मजदूरी देती थी। अब प्रावधानों में बदलाव कर 40 प्रतिशत भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए संभव नहीं है। इसे गरीब और मजदूर वर्ग के साथ अन्याय बताया।

इस दौरान कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष गुड्डन पांडे, नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, पूर्व नपाध्यक्ष नीलम गांधी और नेहा चावरे भी उपस्थित रहीं।

रेत माफ़िया द्वारा डराने धमकाने के मामले में एल एल पी, कंपनी ने की निष्पक्ष जांच की मांग

नर्मदा पुरम मेसर्स वेलोसिटी माइनिंग वर्क्स एल एल पी कंपनी द्वारा नर्मदापुरम -2 समूह में स्थित 34 रेत खदानो का टेंडर 85 करोड रुपये सालाना मे शासन से रेत उत्खन्न एवं परिवहन के लिये ठेके पर लिया गया है। जिसमे नर्मदापुरम तहसील एव सिवनी मालवा तहसील स्थित 34 रेत खदाने आती है। कुछ दिन पूर्व 31 जनवरी को कजलास एव टिगारिया ग्राम मे जो रेत को लेकर विवाद हुआ है। उसमे सही घटना इस प्रकार है। कि ग्राम कजलास एव टिगारिया मे पिछले 1 वर्ष से अवैध रूप से ट्रेक्टर-ट्रॉलियो से रेत का अवैध उत्खनन एव परिवहन गाँव के रेत माफियाओं के द्वारा किया जा रहा था। 31 जनवरी को कंपनी के कर्मचारी ग्राम कजलास एव टिगारिया के पास मिसरोद स्थित गाव मे मैन रोड से निकल रहे थे। उक्त समय गांव के अवैध द्वारा दो ट्रेक्टर से हमारी कंपनी की स्कॉपियो मे जोरदार टक्कर मारी गई जब कंपनी के कर्मचारी गाडियो से नीचे उतरे तो ग्रामीणो ने पथराव चालू कर दिया।

वायरल वीडियो में सिर्फ एक पक्ष ही दिखाया जा रहा है। जबकि मिसरोद मे ही रॉयल्टी काउन्टर पर इन्ही अवैध रेत माफिया द्वारा 1 वर्ष पूर्व नाके को जला दिया गया था। जबकि इन्ही दोनो गाँव से प्रतिदिन 40 से 50 ट्रेक्टर ट्रॉली बिना रॉयल्टी के बाजार में बेची जा रहे थे । इन्हीं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण घटना ग्रामीण द्वारा उस दिन रात्री मे ट्रेक्टर को जलाना बताया जा रहा है उसे दिन रात के के समय सभी कर्मचारी ऑफिस केम्पस मे कैमरों की मे मौजूद थे जिसकी फ़ोटो वीडियो मौजूद है। ओर जिस गाँव मे दिन दहाडे अवैध रेत माफिया के द्वारा इतना उत्तपात मचाया जाता है उस गाँव मे कोई कर्मचारी नौकरी करने वाला ट्रेक्टर जलाने जाने की क्या हिम्मत नहीं कर सकता है? इन लोगो के द्वारा खेती किसानी के नाम पर ट्रेक्टर उठा लिये जाते है उस रात भी इन्ही लोगो द्वारा ट्रेक्टर में आग लगाई गई है। और या तो संभवत: आपसी रंजिश मे ट्रेक्टर को आग के हवाले किया गया है। जिससे पूरी बात कंपनी पर आ जाये।

जिले के स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने के प्रयास किये जाये

स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग समन्वय के साथ करें कार्य, जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

सतना। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि मैदानी क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य विभाग के अमले को महिला बाल विकास के आवश्यक समन्वय से योजनाओं एवं कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन कर जिले के स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी और विकासखण्ड के स्वास्थ्य अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और नियमित मानीटरिंग करें। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला, डीएचओ डॉ. विजय आरख, डॉ. नलिनी शुक्ला, डॉ. मंजू सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह सहित डीपीएम, डीसीएम, बीएमओ, सीडीपीओ उपस्थित थे।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सम्पूर्ण टीकाकरण की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पिछले वर्ष जो भी कमी रही उनकी पूर्ति कार्ययोजना बनाकर सफल क्रियान्वयन करें। टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी बीपीएम की भी रहेगी। विकासखण्ड में सक्षम सुपरवाइजर से बीईई का कार्य ले। सभी बीएमओ एक सप्ताह में टीकाकरण की समीक्षा करें। मझगवां, उचेहरा, सतना अर्बन में 227 बच्चे जीरो डोज से छूटे है। इन स्थानों पर संबंधित एएनएम के खिलाफ सीएमएचओ कार्यवाही करे। स्वास्थ्य में टीकाकरण महत्वपूर्ण प्राथमिकता का कार्य है। बीसीएम को एक माह में 24 विजिट करनी चाहिए। इसके अलावा डीसीएम, बीसीएम भी नियमित रूप से विजिट करें। नागौद के बीसीएम राजेश अहिरवार द्वारा अक्टूबर-नवम्बर माह में विजिट नहीं करने और बैठक में भ्रामक जानकारी दिये जाने पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बीसीएम नागौद का नो वर्क-नो पे आधार पर एक हफ्ते का वेतन काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अगली बैठक तक डीसीएम, बीसीएम, बीपीएम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायेंगे तो कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कलेक्टर ने कहा कि जिले से लेकर मैदानी स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी अपनी मानसिकता बदले और अपनी जिम्मेदारियों को समझें तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। ब्लाक स्तर पर महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठकें हो और उनमें सीएमएचओ के साथ डीसीएम भी उपस्थित हो। अनमोल पोर्टल पर ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन और होम बेस्ड न्यू बार्न केश में सुधार आना चाहिए।

पुलिस ने पकड़ा भारी मात्रा में अवैध गांजा, पांच आरोपी गिरफ्तार

पन्ना। पन्ना पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वन्दना चौहान के मार्गदर्शन में मे थाना प्रभारी पवई एवं देवेन्दनगर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) लिये पाये जाने पर 05 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पन्ना जिले के जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, विक्रय, उत्पादन एवं भण्डारण में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशो के पालन मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मे मुखविर तंत्र सक्रिय कर अवैध मादक पदार्थ मे संलिप्त व्यक्तियो पर कार्यवाहियां की जा रही है। थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील अहिरवार को मुखबिर द्वारा

सूचना प्राप्त हुई कि 02 संदिग्ध व्यक्ति पवई बायपास पर नये अस्पताल के पास अपने बोरियों मे जिसमे उड़िया भाषा मे कुछ लिखा हुआ है उसमे स्टील के पाइप लिये हुए है जिसमे अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये होने की प्रबल संभावना है थाना प्रभारी पवई द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. पवई भावना दांगी के मार्गदर्शन पर तत्काल थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर मुखबिर के बताये स्थान पवई बायपास कटनी मार्ग रवाना किया गया। जहां पहुंचकर देखा 02 व्यक्ति अपने साथ बोरियों मे स्टील के पाइप लिये कही जाने के इंताजार मे खडे थे जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूँछताछ पर संदेहियो ने अपना-अपना नाम पता पुलिस टीम को बताया गया। पुलिस टीम द्वारा संदेही व्यक्तियो की बोरियो की तलाशी लिये जाने पर बोरियों मे रखे स्टील के पाइपो को खुलबाकर देखा जिसमे अवैध मादक पदार्थ सूखा गांजा कुल वजनी 8 किलो अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) कीमती करीब 01 लाख 60 हजार रुपये का पाया गया । पुलिस टीम द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना पवई में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा उड़ीसा से सस्ते दामों में पन्ना एवं आसपास के जिलो मे विक्रय हेतु लाया गया था। आरोपी रामगोपाल पटेल पिता जगन पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी झमटुली थाना बमीठा जिला छतरपुर महेन्द्र पटेल पिता काशीराम पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी पठारी थाना बिजावर थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उनि. संतोष यादव को मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि तीन युवक पन्ना जाने वाली बस के इंतजार में सतना बस स्टैण्ड क्षेत्र में खड़े हैं, जिनके पास बैग एवं थैला है तथा उनमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है।

जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी पन्ना एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन मे पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए अनुसार पन्ना-सतना मुख्य मार्ग स्थित सुन्दरा तिराहा पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध बस वाहन को रोककर तीनों संदेहियों को बस से उतारकर तलाशी ली गई। तलाशी मे आरोपियों के कब्जे से कुल 09 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया।

कमिश्नर ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को किया निलंबित

एसआईआर कार्य में लापरवाही एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर हुई कार्यवाही

पन्ना। पन्ना कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के

निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।

दक्षिण पन्ना के वनकर्मियों हेतु वित्तीय जागरूकता सत्र का आयोजन, डाक विभाग की योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी

पन्ना। पन्ना दक्षिण पन्ना वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रैपुरा कार्यालय परिसर में पोस्ट ऑफिस विभाग से अधिकारी अभिषेक खरे एवं लखविंदर सिंह द्वारा वन विभाग के वनकर्मियों के लिए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। रैपुरा रेंज ऑफिसर विवेक जैन ने कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु समन्वय एवं सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वनकर्मियों को विभिन्न डाकघर आधारित बचत एवं निवेश योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अभिषेक खरे ने अपने उद्बोधन में

बताया कि पोस्ट ऑफिस केवल पत्राचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सरकारी गारंटी वाली वित्तीय सेवाओं का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने विशेष रूप से सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट , मासिक आय योजना तथा पोस्ट ऑफिस की इंश्योरेंस योजनाओं के लाभ, ब्याज दर, अवधि और पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं लखविंदर सिंह ने निवेश की सही योजना बनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नियमित बचत और दीर्घकालीन निवेश आर्थिक सुरक्षा की मजबूत नींव है। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक बन सकती है। साथ ही कर्मचारियों को डिजिटल माध्यमों से पोस्ट ऑफिस सेवाओं का लाभ उठाने, ऑनलाइन अकाउंट ट्रैकिंग एवं पेमेंट सिस्टम की जानकारी भी प्रदान की।

ऋषि मिश्रा पत्रकार कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष बने

पन्ना । पन्ना जिले में लगभग 12 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे ऋषि कुमार मिश्रा को पत्रकार कल्याण परिषद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनकी नियुक्ति परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नईम खान की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी द्वारा की गई है जटाशंकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऋषि मिश्रा की घोषणा की गई है ज्ञात हो ऋषि मिश्रा पत्रकार कल्याण परिषद के कार्यक्रमों को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा परिषद से लगातार सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं ऋषि मिश्रा को अध्यक्ष बनाए जाने परिषद के पदाधिकारी इष्ट मित्रों शुभचिंतकों ने बधाई दी है।

मुड़वारी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पंचायत कमेटी का किया गठन

पन्ना। पवई ब्लॉक के मुड़वारी ग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीस खान के मुख्य आतिथ्य में पंचायत कमेटी का गठन, बीएलए 2 का सम्मान एवं मनरेगा बचाओ अभियान के तहत स्थानीय बस स्टैंड प्रांगड़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जिला अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर जोरदार बैंडबाजों फूल मालाओं से मुड़वारी ग्राम के कांग्रेस जनों ने जोरदार स्वागत किया, तत्पश्चात जिला अध्यक्ष ने मंदिर जाकर बालाजी सरकार के दर्शन भी किए। प्रोग्राम की शुरूआत मां सरस्वती एवं इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस

अध्यक्ष अनीस खान, एसआईआर के सतना प्रभारी, आनंद शुक्ला, पवई विधानसभा प्रभारी अजय श्रीवास्तव, केशरी अहिरवार, वसीम खान, राम करण पांडे, डा. सरफराज फारूकी अजय पाल लोधी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र नामदेव, मुकेश बागरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में कामता शर्मा को सर्व सम्मति से पंचायत अध्यक्ष चुना गया। जिसमें महिला अध्यक्ष पार्वती आदिवासी, किसान कांग्रेस हीरा लाल रजक, युवक कांग्रेस राहुल शर्मा, सेवादल राजेश सोनी, एससी मुन्ना चौधरी, एसटी कंधी आदिवासी, एनएसयूआई अशरफ खान, पिछड़ा वर्ग बीरेंद लोधी, अल्पसंख्यक हरिश्चंद्र जैन एवं बाल कांग्रेस का आरिफ मोहम्मद को पंचायत अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुमान सिंह यादव, अरविंद चौरसिया, खुशी लाल चौधरी, जयवीर चौरसिया, धूराम चौधरी, अनीस पिंकू सिद्दीकी, सुमंत पांडे, नसीम खान, शंभू लाल चौधरी, गुलज़ारी प्रजापति, ईश्वर दास जायसवाल, सज्जन सिंगरौल, नत्थू लाल चौधरी, कमलेश प्रजापति, करीम मोहम्मद, वीरेंद्र साहू, रहीश मोहम्मद, मुकेश पाल, शाहिद रजा, रमेश कोरी, प्रदीप विश्वकर्मा, पप्पू साहू, संदीप नामदेव, बली मोहम्मद, सीताराम कोरी, ब्रजेश बाल्मिक, किशोरी बाल्मिक सहित सैकड़ो कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

शहर विकास की जमीनी हकीकत पर नपा अध्यक्ष पंकज चौरे की पैनी नजर

» तीन वार्डों का सघन निरीक्षण, गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के दिए सख्त निर्देश

इटारसी। संध्य प्रकाश-शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सोमवार को विभिन्न वार्डों का सघन निरीक्षण किया। पार्षदों के साथ किए गए इस दौरे में उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों व ठेकेदारों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वार्ड 06 में नाली निर्माण का निरीक्षण, तकनीकी मानकों पर विशेष जोर

निरीक्षण की शुरुआत वार्ड क्रमांक 06 से हुई, जहां पार्षद जिम्मी कैथवास की उपस्थिति में नाली निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। नपा अध्यक्ष ने निर्माण की गुणवत्ता और ढलान व्यवस्था की जांच करते हुए कहा कि नालियों का निर्माण इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में जल निकासी सुचारू बनी रहे और नागरिकों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वार्ड 08 में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सख्ती

इसके बाद वार्ड क्रमांक 08 में पार्षद ज्योति बाबरिया और पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बाबरिया के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष चौरे ने सड़क की मजबूती, मोटाई और फिनिशिंग को लेकर ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़कें केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित उपयोग के लिए बनाई जानी चाहिए। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाएगी।

वार्ड 12 में जनता से सीधा संवाद, टिकाऊ विकास पर बल

वार्ड क्रमांक 12 में पार्षद मंजीत कलोसिया के साथ नाली निर्माण का निरीक्षण करते हुए नपा अध्यक्ष ने स्थानीय निवासियों से भी संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।

इस अवसर पर पंकज चौरे ने कहा,

हमारा लक्ष्य केवल निर्माण कार्य पूर्ण करना नहीं, बल्कि ऐसा टिकाऊ विकास करना है जो वर्षों तक जनता के काम आए। अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक, हम सभी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण और स्थायी हों।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर के हर वार्ड में विकास कार्यों की सतत निगरानी की जाएगी और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश

इस निरीक्षण के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि शहर में चल रहे विकास कार्यों पर प्रशासन की पैनी नजर है। गुणवत्ता, समय-सीमा और पारदर्शिता—इन तीनों बिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए नगर पालिका शहर के समग्र विकास की दिशा में सतत प्रयासरत है।

किसानों को सशक्त बनाने किया जा रहा है तकनीक का प्रभावी उपयोग : डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य में ग्रामीण डेटा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की गई है। उन्नत तकनीक, पारदर्शी डेटा प्रबंधन और केंद्र-राज्य समन्वय से यह पहल किसानों के हित में मजबूत डिजिटल आधार तैयार कर रही है। इससे किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत पर उपस्थित होकर फसल की फोटो लेकर जानकारी सुरक्षित की जा रही है, जिससे फसल संबंधी डेटा पूरी तरह प्रमाणिक हो रहा है। जियो-फेंसिंग तकनीक से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे केवल वास्तविक खेत स्थल पर ही किया जाए। सर्वे डेटा का त्रिस्तरीय सत्यापन एआई/एमएल सिस्टम और पटवारी स्तर पर किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा भी इस डेटा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। डीसीएस डेटा के आधार पर उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में भी सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहे। सर्वे के दौरान ली गई फोटो की प्रामाणिकता और सही लोकेशन की पुष्टि प्रणाली द्वारा की जाती है। सर्वे केवल निर्धारित समयावधि में ही संभव है और समय सीमा के बाहर या मोबाइल समय में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सर्वे स्वतः रुक जाता है। एआई या एमएल एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम किया गया है। फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और योजनाओं के क्रियान्वयन में डेटा-ड्रिवन निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इसमें किसानों की पहचान, भूमि विवरण और योजना संबंधी जानकारी का केंद्रीकृत पंजीकरण एवं सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटल एकीकरण, स्थान आधारित रिकॉर्ड और बहु-स्तरीय डेटा जांच शामिल हैं। प्रत्येक किसान को 11 अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जिससे एक प्रमाणिक और सटीक किसान डेटाबेस (यूनिफाइड डिजिटल प्रोफाइल) तैयार हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री के निर्धारित मानकों का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। एससीए योजना में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025ङ्क26 के लिए 713 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह डिजिटल व्यवस्था डुप्लीकेशन और फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाएगी और भविष्य की सभी डिजिटल कृषि योजनाओं की मजबूत नींव बनेगी। साथ ही, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किसानों को आसान कृषि ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमे को लेकर दिल्ली में मंथन

एसआईटी की रिपोर्ट बनी मुसीबत

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाया या नहीं, इसको लेकर प्रदेश सरकार बुरी तरह फंस गई है। इस मसले पर गुरुवार को दिल्ली में गहन मंथन हुआ। लेकिन सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। गौरतलब है की शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ महीने पहले आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल, शाह प्रकरण में मप्र पुलिस एसआईटी की रिपोर्ट ही बड़ा पेंच है,इसमें मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। यह रिपोर्ट भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सूत्रों के मुताबिक,मंत्री शाह के प्रकरण को लेकर गुरुवार शाम सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन,गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला व सचिव कृष्णवेणी देशावतु भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ यादव गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे। वह दोपहर में महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि के आश्रम पहुँचे एवं उनका आशीर्वाद लिया। डॉ यादव देर शाम दिल्ली पहुंचे। इसके बाद शाह केस को लेकर मंथन हुआ,लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शाह प्रकरण में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सरकार को मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति को लेकर फैसला लेना है। ऐसे में सरकार के पास अब भी तीन दिन की मोहलत है। सूत्रों के अनुसार,मप्र गृह विभाग के अधिकारी बीते दो दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए है। इस दौरान, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों व विधि विशेषज्ञों से बातचीत कर बचाव के तरीकों पर बात की। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार मंत्री शाह से जुड़े केस में अभियोजन स्वीकृति को लेकर फैसला ले। इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई। यह मियाद दो फरवरी को पूरी हो चुकी और बीते तीन दिन से सिर्फ मंथन का दौर जारी है। शाह केस में ना सिर्फ आरोपी मंत्री बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी समय रहते हालात को संभाल नहीं सके। दरअसल,सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली ?थी। इसके आधार पर उसने शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी सरकार से मांगी। लेकिन तब एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। सूत्रों का दावा है कि प्रकरण में समय रहते सक्रियता दिखाई गई होती तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता था। मप्र गृह विभाग के अधिकारी 19 जनवरी को चौकन्ने हुए। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट का खुलासा किया। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि उसने सरकार से अभियोजन की अनुमति मांगी, जो नहीं मिली। एसआईटी के इस खुलासे के बाद,सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को दो सप्ताह की मुकदमे का फैसला लेने का आदेश दिया। रिपोर्ट से साफ है कि एसआईटी ने मंत्री पर लगे आरोपों को पृथम दृष्टया सही पाया। इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। बता दें कि गत 11 मई को मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर महू में विवादित बयान दिया था। बाद में हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया गया। शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे,लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।

ड्रोन स्क्वाड से होगी वन और वन्य जीवों की निगरानी

वन एवं वन्यजीव निगरानी के लिए धार वन मंडल में विशेष ड्रोन स्क्वाड गठित

भोपाल। वन एवं वन्यजीवों की प्रभावी निगरानी और संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य सेधार वनमंडलद्वारा एक विशेषड्रोन स्क्वाड का गठन किया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस यह पहल वन प्रबंधन और आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाएगी। ड्रोन स्क्वाड में दो उन्नत ड्रोन, पर्याप्त बैटरी बैकअप और आपात स्थितियों में टीम की त्वरित तैनाती के लिए एक समर्पित वाहन शामिल है। टीम का नेतृत्व उप वनपाल स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। इसमें दो वन रक्षक और एक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर की तैनाती भी की गई है। यह ड्रोन स्क्वाड वनाग्नि की समय पर पहचान एवं निगरानी, मानवङ्कवन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर नजर रखने, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तथा वानिकी कार्यों के प्रभावी दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल से वन एवं वन्यजीव संरक्षण की प्रक्रिया अधिक सक्षम बनेगी।

चंबल नदी जलीय जीव एवं पक्षियों की वार्षिक गणना के लिए सर्वेक्षण दल हुआ रवाना

भोपाल। चंबल नदी के घाट दांतरदा क्षेत्र में जलीय जीवों तथा प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की वार्षिक गणना के लिये गठित सर्वेक्षण दल को मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त और वनमंडलाधिकारी, मुरैना ने गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सर्वेक्षण चंबल नदी क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक आंकड़ों के संकलन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण दल में वन विभाग के फील्ड स्टाफ के साथ राजस्थान वन विभाग के प्रतिनिधि श्री भानु प्रताप सिंह एवं फील्ड स्टाफ भी शामिल हैं। सर्वेक्षण दल निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ सहित अन्य जलीय जीवों तथा स्थानीय, प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की गणना करेगा। इस अवसर पर अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, श्योपुर श्री संदीप वास्कले, गेम रेंज ऑफिसर, सबलगढ़ श्री दीपक शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति : मुख्य सचिव

राज्य स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी की हुई बैठक

भोपाल। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को राज्य स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं डिजिटल पहलों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के समन्वित प्रयास करें। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताया गया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के 51 जिलों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए 228 बर्थ वेटिंग रूम क्रियाशील हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं की शंकाओं के समाधान हेतु सुमन सखी चैटबॉट को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी अनमोल 2.0 के माध्यम से की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) एवं शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी दर्ज की गई है। बैठक में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. सलोनी सिडाना ने लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। ई-शिशु मॉडल के अंतर्गत एमजीएम इंदौर में वन-हब एवं 16 स्पोक्स के माध्यम से अब तक 947 नवजात शिशुओं को टेली-कंसल्टेशन सेवाएँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत 33,075 निःशुल्क शल्य क्रियाएँ की गईं, साथ ही 1,026 निःशुल्क जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) सर्जरी भी की गई हैं।

टीबी (क्षय रोग) के नोटिफिकेशन एवं उपचार सफलता दर में सुधार के परिणामस्वरूप डीआर-टीबी मृत्यु दर 3.9 से घटकर 3.0 हुई है। वर्ष 2025 में कुल 8,896 पंचायतों को टीबी-मुक्त पंचायत घोषित किया गया। सिकल सेल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 28,541 मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया और एक करोड़ 13 लाख 59 हजार 76 नागरिकों को सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं।

मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारीशर्मा अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित

भोपाल। मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ मुख्य सुरक्षा अधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) श्री अविनाश शर्मा को वर्ष 2025 के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्?मानित किया गया है। श्री शर्मा को उनकी दीर्घकालीन, निष्ठावान एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पदक दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। श्री अविनाश शर्मा ने मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, महत्वपूर्ण शासकीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत समर्पण का प्रतीक है, बल्कि मध्यप्रदेश पुलिस एवं मंत्रालय सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी गौरव का विषय है।

बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिलेगा 50 हजार रूपए तक का इनाम

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर अधिकतम 50 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा। प्रोत्?साहन राशि 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपए का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचना देने वाले को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा तथा बाकि 5 प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि इस योजना में 01 अप्रैल 2025 से अब तक 167 सफल सूचना देने वालों को 02 लाख 06 हजार हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराए गए हैं। साथ ही जांच एवं वसूली की कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी 3000 रुपये प्रोत्?साहन राशि का भुगतान उनके मासिक वेतन में जोड़कर किया गया है। कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व कुल 63 प्रकरणों में पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्?त होने पर 07 सफल सूचनाकर्ताओं को उनके खाते में 2 लाख 18 हजार रूपये की प्रोत्?साहन राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी/ संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी को भी सूचनाकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। उसे सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर एक प्रतिशत प्रोत्?साहन राशि के रूप में दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत?वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजना के तहत दी जाने वाली 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को सभी संबंधितों को समान रूप में दिया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग, भुगतान से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से गोपनीय और ऑनलाइन है। अब सूचनाकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्?त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन) देना अनिवार्य है। योजना में सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : मंत्री वर्मा

सीहोर के नापलाखेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र और धामंदा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया लोकार्पण

भोपाल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे लोगों को उपचार के लिये सुविधाएँ सहज और सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आमजन के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री वर्मा सीहोर के ग्राम नापलाखेड़ी एवं ग्राम धामंदा में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री वर्मा ने ग्राम नापलाखेड़ी में 56.09 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम धामंदा में 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रारंभ होने से क्षेत्रीय नागरिकों को प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, टीकाकरण सहित विभिन्न जांच एवं परामर्श सुविधाएँ स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल उपचार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूक करना भी है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल एवं साफ-सफाई की आदतें अपनाकर अनेक गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पुराने भवनों का उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जा रही है।कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कृषि रथ से किसानों को फसलों में संतुलित उर्वरक एवं नवीन तकनीकों की दी गई जानकारी

भोपाल। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत झाबुआ जिले के 6 विकासखण्ड में निरंतर कृषि रथ के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों के साथ कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रति दिन 3 ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा अभी तक 296 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर लगभग 20250 किसानों से सम्पर्क स्थापित किया गया है। किसानों को उनकी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही कृषि एवं संबंद्ध विषयों पर नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी दी गई। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं उन्हें जायद के मौसम में तिलहनी फसलों की बुवाई करने की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है, साथ ही किसानों को कृषि रथ के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित अनुशंसा अनुसार संतुलित उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती, नरवाई प्रबंधन, फसल बीमा तथा शासन द्वारा उर्वरक वितरण की नवीन वितरण प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उर्वरक वितरण व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। अब उनके रकबे के आधार पर उर्वरक उपलब्धता की जाएगी, किसानों को उर्वरक लेने के लिए अब लम्बी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा साथ ही उनके पंजीकृत मोबाईल फोन पर खाद के उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों जायद मौसम की फसलों की जानकारी के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई यंत्रो जैसे ड्रीप, स्प्रिंकलर आदि के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। टीकमगढ़ ज़िले के सभी विकासखंडों में कृषि रथ एक माह के लिए चलाये जा रहे हैं। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के द्वारा कृषि से सम्बद्ध अन्य विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि कृषि रथ के माध्यम से विभागों में संचालित योजनाओं का कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार प्रसार करें। इसी तारतम्य में कृषि रथ के माध्यम से ग्राम पंचायत गणेशगंज के ग्राम मानिकपुरा में भ्रमण कर कृषकों को प्राकृतिक खेती/जैविक खेती करने के लिये प्रोत्साहित, नरवाई नहीं जलाने और मृदा परीक्षण कराने का महत्व समझाया।

संपादकीय

लापरवाही की जड़ तक पहुंची एसआईटी, अब कार्रवाई की बारी

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पानी में डूब कर एक युवा इंजीनियर की मौत के मामले में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवालों के बीच विशेष जांच दल (एसआइटी) ने सरकार को अपनी रपट सौंप दी है। उसने बचाव कार्य में घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हुए बारह से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। यह बेहद दुखद है कि एक नौजवान जान बचाने के लिए करीब डेढ़ घंटे तक गुहार लगाता रहा और बचाव दल मौके पर मूकदर्शक बने रहे। एसआइटी ने इसे गंभीर मानते हुए दमकल, पुलिस, प्राधिकरण और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए हैं। किसी घटना के तूल पकड़ लेने के बाद सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई को लेकर गंभीर दिखने की कोशिश की जाती है, लेकिन कार्रवाई के निशाने पर आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं, जबकि वास्तविक जिम्मेदार लोगों को कठघरे में नहीं किया जाता। इस लिहाज देखें तो नोएडा में युवक के पानी में डूब जाने की घटना के बाद एसआइटी ने जिस तरह बारह अधिकारियों के खिलाफ अपनी रपट दी है, वह समस्या की जड़ों को पकड़ने की कोशिश है। सवाल है कि सड़क किनारे किसी बड़े गड्ढे में पानी भरा हो, तो उसकी अनदेखी की मूल जिम्मेदारी किस पर जाती है। दरअसल, समस्या और उसके मूल कारणों के साथ-साथ वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की जरूरत है। विडंबना यह है कि निर्माण स्थलों के पास पानी से भरे बड़े गड्ढों से लेकर कई बड़े नाले महीनों तक खुले रहते हैं और वहां अवरोधक, चेतावनी के संकेतक या सुरक्षा घेरा लगाने या अन्य कोई सुरक्षात्मक उपाय करना जरूरी नहीं समझा जाता। क्या इसी अनदेखी का नतीजा कई बार त्रासद नहीं होता? क्या यह उच्च स्तर के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा नहीं होता? हादसे के बाद आमतौर पर सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगते हैं। ऐसे में एसआइटी ने जिस तरह बारह अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है, वह भविष्य में ऐसी घटनाओं या हादसों को रोकने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है।

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

-योगेंद्र योगी

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन—जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी।

इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है।

उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे।

हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से 0.74एष्ट अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर होने से पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में न के बराबर बर्फ गिरी। गढ़वाल में इस साल जनवरी में बर्फबारी का अभाव देखा गया। ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है। कम हिमपात के चलते जटामांसी और कुटकी जैसी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ीबूटियां विलुप्त हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो ड्रॉट या 'बर्फ का सूखा% जैसी स्थिति बन रही है। विशेष रूप से 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं मानव निर्मित हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के फोर लेन रोड बन रहे हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। सिर्फ राजस्व कमाना सब कुछ नहीं। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर ऐसी कमाई हिमाचल के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी।

आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत?

-कमलेश पांडे

भारत की सियासत वैचारिक अकाल से पीड़ित है, जिसका असर हमारे घरेलू कारोबार के अलावा विदेश व्यापार पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। सच कहूं तो राष्ट्र कीआर्थिक स्वायत्तता ही चीन और रूस जैसे देशों के समक्ष गिरवी प्रतीत हो रही है। यह ठीक है कि रूस हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मददगार मित्र है, जिसके द्वारा शोषण किया जाना स्वाभाविक है। लेकिन चीन जैसे मजबूत और पड़ोसी शत्रु देश को इतना भारी कारोबारी लाभ देने के बावजूद यदि हम उसे अपना मित्र नहीं बना पाए तो यह बात सिर्फ यही चुगली करती है कि हमारी आंतरिक दलित और पिछड़ी नीतियों की वजह से भारत रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ता प्रतीत होता हैं। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ यह सवाल दाग रहे हैं कि आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत?

देखा जाए तो भारत का विदेश व्यापार वर्तमान में भारी घाटे में है, जो दिसंबर 2025 में 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विपरीत स्थिति यानी कारोबारी घाटा चीन, रूस, यूएई और इराक जैसे 75 देशों के साथ है जहां व्यापार घाटा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां से आयात निर्यात से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए, हमारा सरकारी प्रयास निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित हैं, लेकिन अधिशेष (सर्विस ट्रेड को छोड़कर गुड्स ट्रेड में) प्राप्त करने का कोई निश्चित समयसीमा नहीं है। वर्तमान स्थिति में भारत का व्यापार घाटा एफवाई 2026 के पहले क्वार्टर में एफटीए देशों के साथ 59ब बढ़कर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, जहां निर्यात 9ब गिरा और आयात 10ब बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में यह 25.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अनुमान 2027 तक -32 अरब डॉलर का है। यानी वर्तमान के साथ साथ निकट भविष्य भी अंधकारमय है।

खासकर रूस, चीन और आसियान जैसे साझेदारों के साथ ही घाटा प्रमुख समस्या बनी हुई है। रूस तो भारत का भरोसेमंद मित्र है, हथियार व तकनीकी आपूर्तिकर्ता है। लेकिन चीन के खिलाफ आसियान देश समूह को संतुलित करने/रखने की नीति हम पर अब भारी महसूस हो रही है।

लुक ईस्ट की नीति भी सफेद हाथी साबित हुई। हां, लाभ देने वाले पश्चिमी देशों को यदि विकल्प दिखाकर काबू में रखना है तो फिर कुछ नहीं कहना। क्योंकि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होते ही अमेरिकी अकड़ ढीली पड़ गई और उसके साथ भी एफटीए हो गया।

हालांकि भारत की कारोबारी चुनौतियाँ यह हैं कि चीन, रूस और कोरिया के अलावा स्विट्जरलैंड, यूएई, इराक जैसे देशों से आयात अधिक है, जबकि अमेरिकी कूटनीतिक व रणनीतिक टैरिफ ने निर्यात प्रभावित किया, जबकि अब इसका खतरा टल गया है क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एफटीए के बावजूद आसियान निर्यात गिरा, और सोना-तेल आयात घाटा बढ़ा रहा। मसलन, लॉजिस्टिक्स, अनुपालन लागत और वैश्विक टैरिफ हमारे विदेश व्यापार की प्रमुख बाधाएँ हैं। फिर भी भविष्य की संभावनाएँ बरकरार हैं। खासकर घाटा कम करने के लिए निर्यात विविधीकरण, जीवीसी एकीकरण और अवसंरचना सुधार आवश्यक हैं, लेकिन पूर्वानुमान 2027 तक भी घाटा दिखाते हैं।

कहना न होगा कि भारत का विदेश व्यापार घाटा मुख्य रूप से चीन, रूस, स्विट्जरलैंड, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ है। दरअसल, यह घाटा ऊर्जा आयात, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल की उच्च निर्भरता के कारण बढ़ रहा है। इसलिए भारत को नीतिगत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन घाटों पर काबू पाना होगा।

सत्ता की निष्कंटक राह बरास्ते सुनेत्रा की ताजपोशी

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनो पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए।

-उमेश चतुर्वेदी

राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है। सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है। फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। पारिवारिक वज्रपात के बीच सिंहासन पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज के सोचने का अपना ढंग है। सियासी हस्तियों से भी उसे सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों को अपनाने की उम्मीद रहती है। सुनेत्रा सामाजिक सवालों से बच नहीं सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी।

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनो पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए। लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखा है। पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभाई है। सवाल उठ सकता है कि अगर सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं। राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की अगुआई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था। अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गए हैं। अजित के न रहने पर यह संख्या 40 रह गई है। लेकिन बीजेपी की चिंता दूसरी है। शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर होकर उभरते। महाराष्ट्र का यह चाणक्य एक बार फिर स्थापित होता और बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो जाती। शरद पवार इतने प्रभावी और सियासी रूप से तिकड़मी हैं कि बीजेपी के लिए संकट बनकर उभर जाते।

उनकी प्रभावी सक्रियता के चलते शिवसेना के गुटों को भी एक करने की वे कोशिश कर सकते थे। भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, लेकिन एकबारगी स्वीकार कर लें कि ऐसा होता तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती। महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली। अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था। अजित की अगुआई वाले जिला परिषद उम्मीदवार उनके न रहने की वजह से थोड़े आशंकित और निराश भी हैं। इस निराशा को कांग्रेस भुना सकती थी। वह एनसीपी के उम्मीदवारों पर डोरे डाल सकती थी और अपने उम्मीदवारों को नए जोश से भर सकती थी। अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरतभरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था। अजित के न रहने के बाद विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है। शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पाए। यह माहौल कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा करती नहीं दिख रही। 2014 के बाद से उसने जिस नैरेटिव युद्ध की शैली को अपनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी युद्ध प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं है कि वह महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की राजनीति के बारे में स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सोचे और स्थानीय समुदायों के लिए उन्हीं के बीच से प्रभावी नेतृत्व उभारे।

मालदीव्स की तर्ज पर आबूधाबी में बन रहे हैं लग्जरी फ्लोटिंग विला

यूएई के आबूधाबी में पर्यटकों के लिए नई लग्जरी जगह विकसित की जा रही है। दरअसल यहां के गास आईलैंड और सादियात आईलैंड के बीच बसे रामहन आईलैंड पर अल्ट्रा लग्जरी रिट्रीट बनाई जा रही है। इसे प्रॉपर्टी डीलर ईगल हिल और मैरियट इंटरनेशनल मिलकर विकसित कर रहे हैं। साल 2029 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना है। इस आइलैंड प्रोजेक्ट पर करीब 28 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहां 50 प्राइवेट लग्जरी फ्लोटिंग बिला बनाए जाने हैं। ये बिला एक से चार नेडरूम वाले होंगे। विला मालदीव में बने फ्लोटिंग विला की तरह होंगे। खास बात ये होगी कि इन विला के पास इस क्षेत्र के पहले फ्लोटिंग विला होने का दजों होगा। विला में बड़े टेरेस, निजी स्विमिंग पूल और बढ़ी-बड़ी खिड़कियां होंगी, जिनसे समुद्र का सुंदर नजारा नजर आएगा। द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाने के लिए यहां मैग्रोव वृक्ष भी लगाए जाएंगे। यह द्वीप ऊपर से देखने पर तितली के आकार का दिखाई देगा।

सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर होगा डिजाइन

फ्लोटिंग विला सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी का शानदार समावेश होंगे। विला को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि लोग घर के हर कोने से बाहर की शांत दुनिया का आनंद ले सकें। इमारत को इस तरह बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी और हवा अंदर आ सके। इससे बिजली की खपत कम होगी।

4 करोड़ वर्गफीट में होने हैं विकास कार्य

रामहन आइलैंड प्रोजेक्ट 4.3 करोड़ वर्गफीट एरिया में फैला होगा। इन विला के अलावा भी कई लग्जरी होटल्स व रिसॉर्ट होंगे। यहां पॉट क्लब और बुटिका भी बनेंगे। अलग-अलग देशों के खाने की चीजों के कई बेन्यू भी होंगे। साथ ही कई एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज एरिया भी विकसित किए जाने हैं। मुख्य भूमि से फ्लोटिंग विला तक जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ेगा फ्लोटिंग विला के अलावा रामहन द्वीप में 1800 स्वतंत्र बिला, 100 मरीना आवास और 1.7 किमी लंबा बाजार भी अनेगा।

कैसे ग्रेट ब्रिटेन यूनाईटेड किंगडम और इंग्लैंड अलग-अलग हैं?

ब्रिटेन, यूनाईटेड किंगडम और इंग्लैंड ये शब्द तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन ये तीनों शब्द एक ही देश के नाम नहीं है। बल्कि अलग-अलग जगहों के नाम है। आज हम जानते हैं कि आखिर कैसे ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड अलग-अलग हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है, वहीं चार देशों से मिलकर बनता है यूके।

ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। यह एक राजनीतिक टर्म नहीं है, बस एक द्वीप मात्र है। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड देशों को साथ में ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। स्कॉटलैंड और वेल्स स्वतंत्र देश नहीं है, लेकिन इन्हें यूके से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। यूनाईटेड किंगडम असल मायनों में यूके ही एक संप्रभु देश है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड मिलकर यूके बनाते हैं। इन चारों देशों के लोगों के पास यूके की ही नागरिकता होती है। यूएन की लिस्ट में भी आपको यूनाईटेड किंगडम का ही नाम मिलेगा। यूके में संसदीय राजशाही चलती है। इंग्लैंड इंग्लैंड यूके में शामिल चार प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, जिसे देश का दर्जा मिला है। इसके पास स्वयं का झंडा व राष्ट्रगान है। लेकिन यूके की संसद जरूरत पड़ने पर इनकी शक्तियां छीन सकती है।

ये हैं दुनिया के कुछ अनोखे रीति-रिवाज

दुनिया के देश भले ही विकसित हो गए हों, पर यहां आज भी कई ऐसी मान्यताएं और त्योहार मनाए जाते हैं जो सुनने-देखने में बेहद विचित्र लगते हैं. आज हम आपको सबसे अजीबोगरीब मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं.

पोल्टरबेंड, जर्मनी

जर्मनी में शादी के दौरान दुल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार चीनी से बने बर्तन तोड़ते हैं। बाद में इन टूटे हुए बर्तनों को नवविवाहित जोड़ा साफ करता है। कठिन समय में वह जोड़ा एक-दूसरे का साथ दे सकें, यही इस परंपरा का मकसद हैं।

ब्लैकेनिंग ब्राइड यूरोप एवं अमेरिका

यह एक प्री-वेडिंग रिवाज है। इसमें दुल्हन के ऊपर दूध, अंडे, काले पदार्थ जैसी चीजें डालकर दुल्हन को शहर में घुमाया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि दुल्हन जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार हो सकें।

वाइफ कैरिंग, चीन

चीन के कई हिस्सों में पति अपनी गर्भवती पत्नी को पीठ पर बैठाकर जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चे की डिलीवरी आसानी से होती है। साथ ही इस रिवाज से पति का पत्नी के प्रति प्यार भी झलकता है।

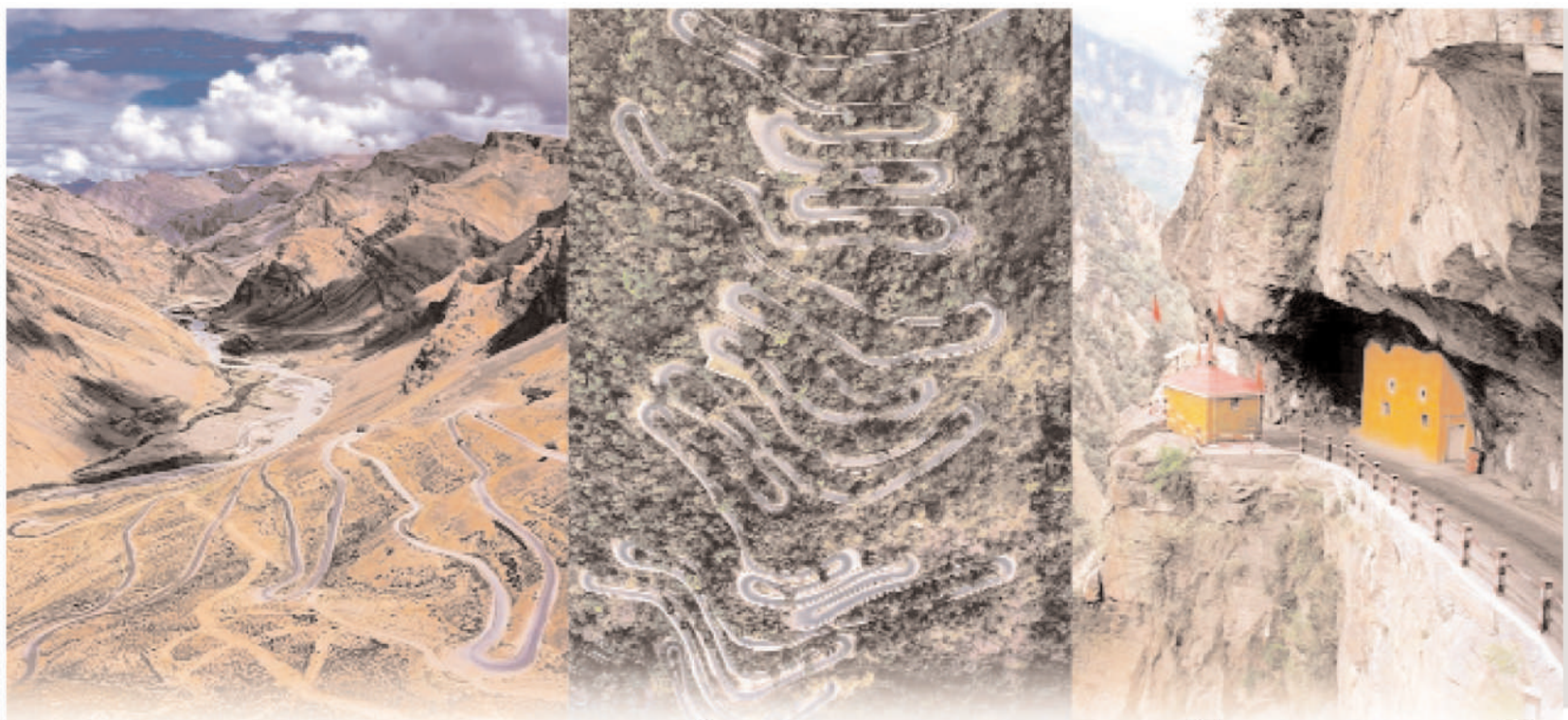

बेहद खतरनाक हैं भारत की ये सड़कें, आसान नहीं यहां गाड़ी चलाना

अक्सर लोग घूमने-फिरने के लिए बाहर जाना पसंद करते थे. वे पहाड़ों और ग्रीनरी वाली जगहों को सेलेक्ट करते हैं, ताकि वे अपना समय शांति में बिता सके. इसी के साथ लोगों को ऐसी खूबसूरत सड़कों पर घूमना, तस्वीरें क्लिक करना और ड्राइविंग-राइडिंग करना बेहद पसंद आता है, लेकिन आज हम आपको भारत की उन सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत के साथ-साथ बेहद खतरनाक है. इन सड़कों पर राइडिंग और ड्राइविंग आपके लिए खतरे से खाली नहीं है.

अक्सर लोग घूमने-फिरने के लिए बाहर जाना पसंद करते थे. वे पहाड़ों और ग्रीनरी वाली जगहों को सेलेक्ट करते हैं, ताकि वे अपना समय शांति में बिता सके. इसी के साथ लोगों को ऐसी खूबसूरत सड़कों पर घूमना, तस्वीरें क्लिक करना और ड्राइविंग-राइडिंग करना बेहद पसंद आता है, लेकिन आज हम आपको भारत की उन सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत के साथ-साथ बेहद खतरनाक है. इन सड़कों पर राइडिंग और ड्राइविंग आपके लिए खतरे से खाली नहीं है. जिन सड़कों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो रास्ते कमजोर दिल वालों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है. ये ऐसी सड़कें हैं जहां चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ के साथ-साथ चिंता और भय के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं. सर्दियों के मौसम की बात करें तो उस समय पर इन सड़कों पर दूर- दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है.

लेह-मनाली हाईवे

इस सड़क पर भूस्खलन जैसी घटनाएं आए दिन ही होती रहती हैं. ये रोड सर्दियों के दौरान बहुत सारी नेविगेशन समस्याओं से ग्रस्त है. मनाली अक्सर लोग घूमने-फिरने जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पैंड करते हैं.

रोहतांग दर्रा

रोहतांग दर्रा जितना देखने में सुंदर है उतना ही यहां पहुंचना कठिन है. ये मनाली से लगभग 53 किमी दूर स्थित है. जो भी यहां विजिट करता है वो घाटी, ग्लेशियर, पहाड़ और चंद्रा नदी का लुत्फ उठा सकते हैं. आपको बता दें ये दर्रा जून और अक्टूबर के महीनों के बीच खुला रहता है और इस ड्यूरेशन में यहां हजारों पर्यटक आते हैं.

गाटा लूप्स

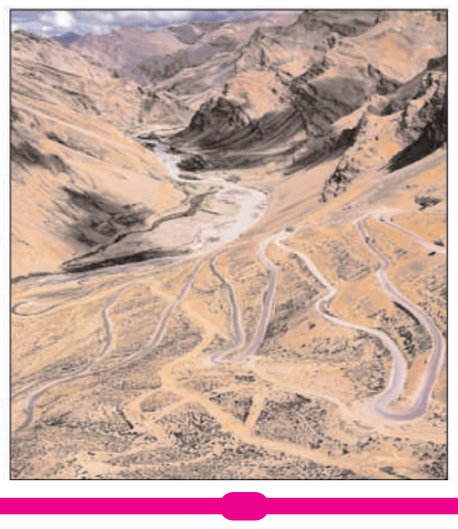

आप सबिह को बता दें जानकारी के मुताबिक इस सड़क में 21 हेयरपिन लूप हैं और यह लद्दाख में सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क की ओर जाता है. इस जगह पर जाने और घूमने के लिए एक ट्रेंड वाहन चालक की जरूरत होती है.

कोली हिल रोड

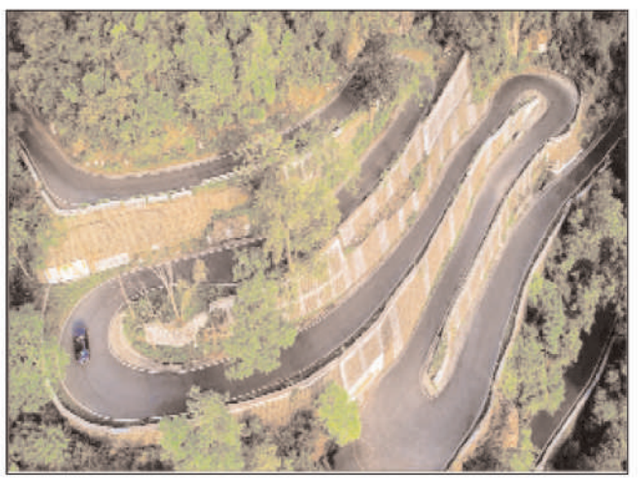

तमिलनाडु राज्य में स्थित इस सड़क पर ड्राइविंग करना खतरे से खाली नहीं है. इस रोड पर लगातार 70 हेयरपिन मोड़ हैं जिसे क्रॉस करना हर चालक के लिए आसान नहीं है. वो ही शख्स यहां पर गाड़ी चला सकता है जिसका पहाड़ों में ड्राइव करने का लंबा अनुभव रहा हो.

सिक्किम में ज़िगज़ैग रोड

यह सड़क तीन स्तरों से गुजरती है जो सिक्किम में एक पहाड़ी घाटी में घूमती है. इस खतरनाक रोड पर हर कोई ट्रेवल करने से कतराता है और तौबा कर लेता है.

सांगला रोड

हिमाचल की सड़क जिसे सांगला रोड के नामसे जाना जाता है ये भी काफी खतरनाक है. इस सड़क पर जरा सी लापरवाही करने का सीधा मतलब यह है कि अपनी जान जोखिम में डालना.

दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर लटकी है चीन की यह दुकान

चीन के हुनान प्रांत में ऊंची पहाड़ी पर एक अनोखी दुकान (गुमटी) बनी है, जो 120 मीटर (393 फीट) की ऊंचाई पर पहाड़ के बीच में है। यह दुकान पर्वतारोहियों को उनकी चढ़ाई के दौरान आवश्यक नाश्ता, जलपान और भोजन प्रदान करता है। इसे पूरी दुनिया में सबसे असुविधाजनक सुविधा स्टोर करार दिया गया है। आमतौर पर हमें कोई खाने की चीज लेनी हो तो आसानी से किसी दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चीन में एक ऐसी दुकान है, जहां से सामान खरीदने के लिए ग्राहकों को जान की बाजी लगानी पड़ जाती है। दरअसल यह दुकान हुनान प्रांत में शिनियुझाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में स्थित है। यह दुकान एक पहाड़ पर 393 फीट की ऊंचाई पर है। ये मात्र 22 वर्गफीट में ही फैली हुई है। इसे दुनिया की सबसे असुविधाजनक सुविधा स्टोर कल्त्य जाता है। संभवतः यह दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित दुकान है। दुकान एक लकड़ी के बक्से में बनी हुई है। यहां दो घंटे की चढ़ाई के बाद पहुंच सकते हैं

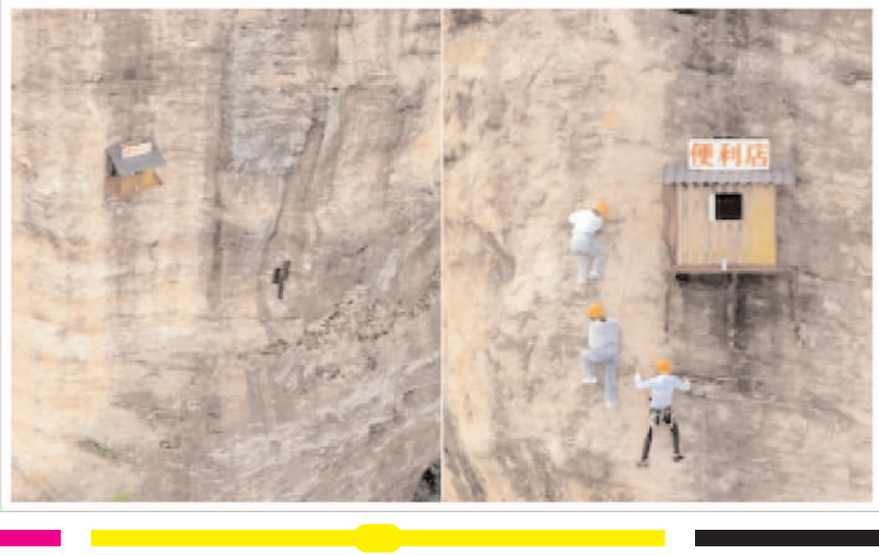

पवर्तारोहियों की मदद के लिए खोली गई दुकान

यह दुकान पर्वतारोहियों को पहाड़ चढ़ने के दौरान रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराने के मकसद से खोली गई है। यहां पर कुछ तरह की डिंक्स, पानी और चिप्स जैसी चीजें मिलती है। यहां काम कर रहे वर्कर बताते हैं कि यहां चीजें महंगे दामों पर नहीं बल्कि नीचे मिल रही कीमतों पर ही मिलती हैं। इसलिए दुकान आने वाले लोगों में कृतज्ञता का भाव भी होता है। दुकान में एक समय में एक व्यक्ति ही खड़ा रह सकता है। उसी को हर सुबह दुकान में सामान भरना होता है। इसमें दो घंटे का समय लग जाता है। स्टोर तक की चढ़ाई में ही 90 मिनट लगते हैं। यहां काम कर रहे कर्मचारी जरूरत पड़ने पर पहाड़ चढ़ रहे लोगों की मदद भी करते हैं।

चितरंगी बाजार से गायब हुई 18 वर्षीय रजवंती, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी

सिंगरौली। चितरंगी थाना क्षेत्र से 18 वर्षीय युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। चितरंगी बाजार से बिना बताए निकली युवती घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।

थाना चितरंगी से मिली जानकारी के अनुसार सूचना देने वाली फुलकली उर्फ फुलमती सिंह गोड पति स्वर्गीय सीताराम सिंह गोड (50 वर्ष), निवासी ग्राम बूढ़ाडोल टोला खरिका ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रजवंती सिंह गोड उम्र 18 वर्ष 6 माह गांव की ही मानवती सिंह गोड के साथ चितरंगी में रहकर सीएम राइज स्कूल में मजदूरी का कार्य करती थी। 3 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे रजवंती घर पर नहीं थी। इसी दौरान मानवती सिंह गोड ने फोन कर बताया कि रजवंती बिना बताए चितरंगी बाजार की ओर चली गई है। सूचना मिलने के बाद परिजन शाम करीब 8 बजे चितरंगी बाजार पहुंचे और रिश्तेदारों व परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चला। परिजनों ने बताया कि रजवंती के पास मोबाइल फोन नंबर 6264074047 था, लेकिन लगातार कॉल करने के बावजूद फोन रिसीव नहीं हुआ। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवती का कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजन थाना चितरंगी पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार युवती का हुलिया - रंग सावला, कद एकहरा, देहाती भाषा बोलने वाली, आठवीं कक्षा तक शिक्षित है। लापता होने के समय उसने हरे रंग का सलवार-कुर्ता पहन रखा था। थाना चितरंगी में गुम इंसान क्रमांक 08/2026 दिनांक 4 फरवरी 2026 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों को सूचना भेजते हुए युवती की तलाश में सहयोग मांगा है। पुलिस का कहना है कि संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है और मोबाइल लोकेशन सहित अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। वहीं परिजन बेटी की सुरक्षित वापसी को लेकर बेहद चिंतित हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है।

रेडक्रॉस सोसायटी की आम सभा बैठक स्थगित

सिंगरौली। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, सिंगरौली के समस्त सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सोसायटी द्वारा 11 फरवरी को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। किन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त वार्षिक आम सभा की बैठक को स्थगित किया जाता है। बैठक की आगामी तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत इसकी सूचना समस्त सदस्यों एवं संबंधित व्यक्तियों को पृथक रूप से समाचार पत्रों, आधिकारिक व्हाट्सएप समूह तथा अन्य उपयुक्त माध्यमों के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

महान सीएचपी में देर रात दिखा तेंदुआ, फैक्ट्री प्रशासन अलर्ट

सिंगरौली । महान स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कोल हैंडलिंग प्लांट में देर रात तेंदुआ देखे जाने से फैक्ट्री परिसर में ह?कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुए की आवाजाही वहां लगे सीसीटीव्ही में रिकॉर्ड की गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है और कर्मचारियों व ठेका श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं।

फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जारी सूचना में बताया गया कि तेंदुआ सीएचपी क्षेत्र में देर रात देखा गया, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे फैक्ट्री परिसर में अनावश्यक आवाजाही न करें और केवल निर्धारित गेटों से ही प्रवेश व निकास करें। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि परिसर के भीतर पैदल चलने, साइकिल या दोपहिया वाहनों के उपयोग पर रोक रहेगी तथा केवल अधिकृत चारपहिया वाहनों का ही उपयोग किया जाए। साथ ही सुबह और शाम के समय खुले में घूमने से बचने और सुनसान क्षेत्रों में अकेले जाने से मना किया गया है। सुरक्षा विभाग और वन विभाग को भी अलसुबह मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाते हुए जानकारी एकत्रित करने में लगी है। फैक्ट्री प्रशासन ने सभी कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रबंधन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा टीम तैनात है।

कोयला लदे टेलर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत, नेशनल हाईवे जाम

सिंगरौली। जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ोखर गांव में आज दिन गुरूवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बड़ोखर गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रेलर वाहन ने बाइक को कुचल दिया। मृतकों की पहचान बलिराम साकेत और उनकी पत्नी सुनीता साकेत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों शाम करीब 5 बजे कसर की ओर से अपने घर बड़ोखर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दंपती की बेटे की शादी होने वाली थी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और मुआवजे व कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही बरगवां थाना निरीक्षक मो. समीर, मोरवा निरीक्षक कपूर त्रिपाठी तथा गोरबी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइस दी जा रही है और जाम खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

राज्य पुलिस एवं आर्मी डिफेंस कोचिंग प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया आज से

सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल विध्यनगर द्वारा सीएसआर के सौजन्य से जिले के युवक एवं युवतियों के व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार प्राप्ति के लिए तीन माह का डिफेंस, आर्मी, पैरामिलिट्री एवं राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन के लिए कोचिंग एवं शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. एवं दीप ज्ञान कोचिंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कोचिंग प्रशिक्षण में चयन के लिए कल दिन शनिवार 6 एवं 7 फरवरी को चूनकुमारी स्टेडियम बैढ़न सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जायेगा। इक्षुक प्रतिभागियों निर्धारित समयानुसार उपस्थित होकर चयन के लिए आवेदन कर सकते है।

सड़क के लिए तरस रहा करही खाड़ी टोला, दशकों से कच्चे रास्ते पर गुजर रही जिंदगी

चुनाव में वादे, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस, ग्रामीणों में बढ़ता आक्रोश

सिंगरौली । जनपद पंचायत बैढ़न अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरा के करही खाड़ी टोला में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधा सड़क से वंचित हैं। करीब एक सैकड़ा घरों और 700 से 800 की आबादी वाले इस टोले में सड़क पूरी तरह कच्ची है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में स्थिति बेहद भयावह हो जाती है, जब कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग फिसलकर घायल हो चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तक शिकायत की जा चुकी है। चुनाव के समय लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी गांव में पहुंचकर पक्की सड़क बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे भी अधूरे रह जाते हैं। दशकों से ग्रामीण इसी कच्ची सड़क के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम भरोसे गुप्ता समेत करीब 38 ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का निराकरण किए बिना ही शिकायतों को क्लोज कर दिया गया। इससे ग्रामीणों में गहरा असंतोष और नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि करही खाड़ी टोला में जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यदि शीघ्र ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

ननि अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्षदो की सर्वदलीय बैठक आयोजित

बैठक में निगमाध्यक्ष ने नगर विकास से जुड़े मुद्दो पर की विस्तार से चर्चा एवं दिए उचित निर्देश

सिंगरौली

नगर पालिक निगम के अध्यक्ष देवेश पाण्डेय की अध्यक्षता में नगर निगम के पार्षदो के साथ सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में पार्षदो द्वारा निगम, परिषद की बैठक निर्धारित समय पर कराने के लिए कहा गया, ताकि नगर विकास से संबंधित कार्यो की परिषद के माध्यम से गति दी जा सके। वही निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुये साफ -सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में संचालित सीवर लाईन के कार्यो की पर चर्चा करते हुये। सीवर लाईन कार्य को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने एवं जहां की स?के क्षतिग्रस्त हो गई है, उनकी तत्काल मरम्मत कराने के लिए निर्देश निगम अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

बैठक में गनियारी शापिंग प्लॉजा की बन्द पड़ी दुकानो के संबंध में चर्चा करते हुये निर्माण कार्य आ रही कठिनाईयो को दूर कर प्रारंभ कराने के लिए निर्देशित किया गया। वही सिविक सेन्टर निर्माण कार्य, जिसमें लगभग 200 दुकाने बननी है एवं इनडोर स्टेडियम बनाने के साथ ही ऑटोडोरियम का भी निर्माण होना है, जल्द निर्माण कराया जाए। जिससे नगर निगम का राजस्व वृद्धि होगी। मोबाईल टॉलेट चलित शौचालय की संख्या आबादी के अनुसार बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में निगाही मोड से दुधिचुआ, म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा तक फोरलेन सड़क निर्माण कराये जाने के लिए चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत अमृत जल योजना में छूटे हुये वार्डो, कॉलोनियों को शामिल करने के लिए निर्देशित किया तथा मोरवा जोन में एक शव वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही टैंकरों की उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत प्रमुख जगह जैसे नवजीवन विहार चौराहा, बैढ़न बस स्टैड क्षेत्र, माजन मोड़, निगाही मोड़ एवं अन्य स्थानों में तत्काल अतिक्रमण हटाये जाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।

बैठक में नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक भवन का संचालन एवं रखरखाव निगम द्वारा कराये जाने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में ननि अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए नगरीय क्षेत्र की जनता ने हम सब को जिम्मेदारी सौपी है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक नगारिक की आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनकी पूर्ति करायें, ताकि आम जन मानस के जीवन में सुधार लाया जा सके। आप सब अपने वार्डो की मूलभूति सुविधाओ को चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यकता आनुसार वार्डो में कार्यो को कराया जा सके। बैठक के दौरान पार्शद भारतेन्दु पाण्डेय, अखिलेश सिंह, शेखर सिंह, सीमा जायसवाल, राम नरेश शाह, श्याम कुमारी शर्मा, संजय सिंह, सावनमती कुशवाहा, अनारकली, चन्दा देवी, नीलू कुमारी, रूकमन देवी, राज बहादुर पनिका, राम मिलन भारती, देवमती बाबुनंदन बंसल, आषीश कुमार बैस, रविन्द सिंह, संतोष शाह, बबली शाह, लालसा यादव, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर आरपी बैस मौजूद रहे।

जिला स्तरीय ओलंपियाड में सिंगरौली के 32 छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

मॉडल स्कूल चितरंगी की चंचल सिंह ने हिंदी-अंग्रेजी में पाया प्रथम स्थान

सफल विद्यार्थियों को कलेक्टर करेंगे सम्मानित, ग्रामीण प्रतिभाओं ने बढ़ाया जिले का मान

सिंगरौली । राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आयोजित जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 16 एवं 17 जनवरी को आयोजित इस परीक्षा में जिले के कुल 32 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। इनमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चितरंगी के 9 विद्यार्थी, प्राथमिक शाला नवानगर के 2, माध्यमिक शाला गड़वानी के 2 तथा हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ौरा के 2 विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त हायर सेकेंडरी स्कूल बगैया, हायर सेकेंडरी स्कूल निवास, माध्यमिक शाला सरहा, माध्यमिक शाला पाठरीदह, माध्यमिक शाला हरदी, नवीन माध्यमिक शाला बडरम, प्राथमिक शाला मड़वा, माध्यमिक शाला पिड़रिया, प्राथमिक शाला बीछी, माध्यमिक शाला माडवारी टोला, प्राथमिक शाला ईटार, माध्यमिक शाला परसोहर तथा माध्यमिक शाला महुआगड़ी कोठार से भी एक-एक छात्र ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चितरंगी की छात्रा कुमारी चंचल सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ौरा की छात्रा छाया चतुर्वेदी ने कक्षा 8वीं में संस्कृत और विज्ञान विषय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और जिले का गौरव बढ़ाया है। विशेष बात यह है कि अधिकांश सफल विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी चयनित छात्रों को मोमेंटो, प्रमाण पत्र एवं ट्रैकसूट प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस सफलता से जिले के विद्यालयों में हर्ष का माहौल है।

एनटीपीसी सिंगरौली संभागीय नाट्य समारोह में दिल की दुकान ने जीता दर्शकों का दिल

मंच पर उतरी मानवीय संवेदनाएँ, दिल की दुकान ने छोड़ी गहरी छाप

सिंगरौली। उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के सौजन्य से आयोजित संभागीय नाट्य समारोह के अंतर्गत एनटीपीसी सिंगरौली के कर्मचारी विकास केंद्र में प्रसिद्ध नाट्य कृति दिल की दुकान का सफल एवं प्रभावशाली मंचन किया गया। इस नाटक के लेखक राजेंद्र शर्मा हैं तथा निर्देशन रतन राठौर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अनुभूति नाट्य इकाई, कानपुर द्वारा प्रस्तुत यह हास्य नाट्य प्रस्तुति मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों की जटिलताओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत प्रभावी ढंग से दर्शाने में सफल रही।

इस अवसर पर प्रज्ञा नायक, अध्यक्षा, वनिता समाज, सीएच किशोर कुमार महाप्रबंधक, विभिन्न विभाग प्रमुख, प्रशांत, कार्यक्रम प्रभारी, संगीत नाटक अकादमी, दिनेश श्रीवास्तव कार्यक्रम ऑब्जर्वर, संगीत नाटक अकादमी, वनिता समाज की वरिष्ठ सदस्याएं, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, प्राचार्यगण, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। नाटक की कथावस्तु ने आधुनिक जीवन में मानवीय भावनाओं के बदलते स्वरूप को गहराई से प्रस्तुत किया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय, भावपूर्ण संवाद एवं सशक्त मंच-सज्जा के माध्यम से प्रत्येक पात्र को जीवंत बना दिया। प्रस्तुति के दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

चितरंगी बाजार से हटाया गया वर्षों पुराना अतिक्रमण, सड़क हुई सुगम

तहसीलदार की कार्रवाई से स्कूल और बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार

सिंगरौली । शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितरंगी के सामने वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह के नेतृत्व में हटाया गया। यह कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की गई। अतिक्रमण हटने से चितरंगी बाजार की मुख्य स?क पर यातायात सुचारू हुआ और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

बताया गया कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा स?क के दोनों ओर अस्थायी दुकानें, ठेले और शेड लगाकर लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था। इसके कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। विशेषकर सुबह और शाम के समय स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना प?ता था। विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों द्वारा कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी कि अतिक्रमण के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। भारी वाहनों और दोपहिया वाहनों के एक साथ गुजरने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कराई।

प्रशासनिक टीम ने पहले व्यापारियों को समझाइस दी और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। इसके बाद नियमानुसार अवैध निर्माण और ठेलों को हटाया गया। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण रोजाना घंटों जाम लगता था। अब स?क खुलने से आवागमन आसान हो गया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यह कार्रवाई एक बार की न होकर नियमित रूप से की जाए, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके। तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे निर्धारित सीमा में ही अपनी दुकानों का संचालन करें और सड़क को बाधित न करें। प्रशासन द्वारा आगे भी निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। इस कार्रवाई से चितरंगी बाजार में यातायात व्यवस्था सुधरने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध हुआ है।

धनुष से शादी की खबरों के बीच सिद्धांत चतुर्वेदी ने मृणाल ठाकुर को चिढ़ाया

'आप किसी और की दुल्हन हैं'

मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में हैं। उनका नाम अभिनेता धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है और दोनों की शादी तक की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच मृणाल ठाकुर अपनी आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही फिल्म में मृणाल के को-स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने मृणाल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जो अब वायरल है। 'दो दीवाने सहर में' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मृणाल और सिद्धांत एक-दूसरे से मजाक करते नजर आए। इसी दौरान सिद्धांत चतुर्वेदी ने मृणाल को लेकर एक मजाक किया। दरअसल, सिद्धांत से उनके वैलेंटाइन डे को लेकर सवाल किया गया। इसी पर जवाब देते हुए सिद्धांत ने कहा कि फिलहाल वो सिंगल हैं। तभी फिल्म के पोस्टर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल ये ही दुल्हन है। तभी वहां खड़ी मृणाल को संबोधित करते हुए सिद्धांत ने कहा, 'आप तो किसी और की दुल्हन हैं।' इस पर वहां मौजूद सभी हंसने लगे। मृणाल ने भी सिद्धांत के इस मजाक पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक पल और ऐसा आया, जब सिद्धांत ने मृणाल के धनुष से कनेक्शन पर कमेंट किया। दरअसल, इवेंट में मौजूद किसी ने चेन्नई को लेकर सवाल किया। इस पर सिद्धांत ने मृणाल की ओर इशारा करते हुए पूछा, 'चेन्नई वाला सवाल इनसे था या मुझसे?' मृणाल और वहां मौजूद बाकी लोग जल्द ही सिद्धांत के इस मजाक को समझ गए और हंसने लगे। वहीं मृणाल सिद्धांत के इस मजाक पर ब्लश करती नजर आईं। धनुष के साथ रिलेशनशिप और शादी की चर्चाओं के बीच सिद्धांत का मृणाल को लेकर इस तरह का मजाक करना और अभिनेत्री का सिर्फ ब्लश करके और मुस्कुराकर इनको टालना, एक बार फिर दोनों के रिलेशन को लेकर हिंट देता है। पिछले काफी वक्त से मृणाल ठाकुर का नाम धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों दोनों के जल्द ही शादी करने की चर्चाएं भी सामने आईं। हालांकि, मृणाल ठाकुर ने इन खबरों को सिर्फ अफवाह ही बताया। पिछले एक इंटरव्यू में भी इस बात का मजाक उड़ाते हुए अभिनेत्री ने कहा कि शादी की डेट तक आई और मुझे इनवाइट भी नहीं किया गया। कम से कम मुझे भी इनवाइट कर देते। लेकिन इस बीच अब सिद्धांत का इवेंट में इस तरह मृणाल को धनुष को लेकर छेड़ना, कुछ और ही बयां करता है। रवि उदयवार द्वारा निर्देशित 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म एक तयशुदा शादी से पनपे रिश्ते की पड़ताल करती है, जिसमें दो अजनबी लोगों के बीच की अटपटी शुरुआत, दोस्ती, भावनात्मक घनिष्ठता और जटिल विकल्पों के बीच के सफर को दिखाया गया है। फिल्म में मृणाल और सिद्धांत के अलावा इला अरुण, आयशा रजा, जॉय सेनगुप्ता और अचिंत कौर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।

फिल्म के बाद सिंगिंग में डेब्यू, राशा थडानी ने फिल्म लईकी लईका में गाया गाना

राशा थडानी ने अपनी आने वाली फिल्म 'लईकी लईका' के गाने 'छाप तिलक' से सिंगिंग में भी डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनके साथ अभय वर्मा भी हैं। राशा ने हाल ही में सिंगिंग करने से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस एक इंटरव्यू में साझा किया है। उन्हें इसे सपने के सच होने जैसा बताया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में राशा थडानी बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है। वह कहती हैं, 'मैं जब 5 साल की थी, जब मैंने उस्ताद कादिर मुस्तफा खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। इसके अलावा मैंने जैज म्यूजिक भी सीखा है। म्यूजिक मेरे लिए एक तरह का सुकून है। जब मैं रियाज करती हूं, तो वो एक घंटा सिर्फ मेरा होता है। मैं हमेशा से गाना चाहती थी, यही मेरा पैशन रहा है। लेकिन मैं पूरी तरह एक शॉवर सिंगर हूं। आज मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।' राशा थडानी ने फिल्म लईकी लईका में जो गाना गया है, उसके बारे में जानकारी साझा की है। इस गाने को भगवान शिव को समर्पित किया है। वह कहती हैं, 'मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है। मेरे लिए भगवान शिव सिर्फ एक भगवान नहीं, जिंदगी का हिस्सा हैं। वो हर दिन मेरे साथ रहते हैं। इस गाने में जब डमरू की बात होती है, तो मुझे नटराज का नृत्य याद आता है। भगवान शिव कला और नृत्य के देवता हैं। यह गाना उन्हीं को समर्पित है। मेरी कला उन्हीं की है।' हाल ही में एक्टर प्रभास ने राशा थडानी की आवाज की तारीफ की है। राशा ने इस तारीफ को कॉन्फिडेंस बूस्टर बताया। वह कहती हैं, 'प्रभास मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी बहुत सिंपल और सपोर्टिव हैं। उनसे थोड़ा भी मोटिवेशन मिलना, मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है।' राशा थडानी की फिल्म लईकी लईका की बात करें तो यह एक रोमांटिक-एक्शन फिल्म है। यह फिल्म 2026 के समर सीजन में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'मयसभा' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

'बॉर्डर 2' के आगे कमजोर पड़ी 'मर्दानी 3'

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों के बीच अब भी क्रेज बरकरार है। फिल्म को सिनेमाघरों में 13 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म 300 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' को भी थिएटर में 6 दिन पूरे हो चुके हैं। इन दो फिल्मों के अलावा जावेद जाफरी की फिल्म 'मयसभा' भी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने की कोशिश कर रही है। जानिए, बुधवार को इन फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा।

सैकनिल्क के अनुसार फिल्म 'मर्दानी 3' ने छठे दिन 2 करोड़ रुपये की कमाई की है। जबकि फिल्म ने पांचवें दिन 2.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म का कुल कलेक्शन भी अब तक 24.25 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। इसमें वह जबरदस्त एक्शन करती नजर आई हैं।

सैकनिल्क के अनुसार फिल्म 'बॉर्डर 2' ने तेरहवें दिन यानी बुधवार को 4 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं मंगलवार को 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। बुधवार को इसका कलेक्शन कम हुआ है। लेकिन यह फिल्म वीकएंड पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है। 'बॉर्डर 2' फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक 290 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म जल्द ही 300 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। जबकि मेकर्स ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनकी फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'मयसभा' में लीड रोल में जावेद जाफरी हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को चौंकाया है। लेकिन 'मयसभा' कलेक्शन के मामले में काफी कमजोर साबित हुई। इस फिल्म ने छठे दिन सिर्फ 6 लाख रुपये कमाए, जबकि पांचवें दिन सिर्फ 7 लाख रुपये कमाए थे। 'मयसभा' फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक 73 लाख रुपये हो चुका है। फिल्म 'तुम्बाड़' फेम डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने इस फिल्म को बनाया है।

सात साल बाद अभिनय में वापसी पर क्या बोलीं रिया चक्रवर्ती? वीडियो शेयर कर साझा की दिल की बात

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपकमिंग सीरीज %फैमिली बिजनेस% से स्क्रीन पर सात साल बाद वापसी कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के एलान के बाद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने अपने काम पर लौटने के लंबे सफर के बारे में बताया। उन्होंने पर्दे पर वापसी के लिए आभार जताया है। हाल ही में रिया ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह तैयार हो रही हैं। एक्टिंग में दोबारा वापसी करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आखिरी बार 2019 में चेहरे के लिए शूटिंग की थी। रिया ने कहा, 7 साल। यह सच में बहुत अजीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से एक्टिंग करूंगी। यह अविश्वसनीय है क्योंकि यह एक सपने जैसा है। जब मैं 17 साल की थी, तब यह मेरा सपना था। फिर वह सब हुआ। इसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। फिर मैं वापस आ गई। हालांकि अब मैं बहुत बदल गई हूं। अब मेरा एक अलग करियर है। अब कई मायनों में यह मायने नहीं रखता। कई मायनों में यह अभी भी पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पोस्ट के कैप्शन में रिया ने लिखा सेट पर गए हुए 7 साल हो गए हैं। हालांकि मैं आज भी वही लड़की हूं जो 17 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी।

'मैं अभी प्यार में पड़ रहा हूं', दिशा पाटनी को डेट करने की खबरों पर सिंगर तलविंदर ने पहली बार दी प्रतिक्रिया

पंजाबी सिंगर तलविंदर इन दिनों अपने गानों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं। तलविंदर का नाम इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा पाटनी तलविंदर को डेट कर रही हैं। अब डेटिंग की खबरों पर तलविंदर ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। जानिए तलविंदर ने दिशा को डेट करने पर क्या कुछ कहा?

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में तलविंदर ने डेटिंग की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनकी दिशा पाटनी से मुलाकात कब हुई थी। सिंगर ने बताया कि उनकी और दिशा की मुलाकात हाल ही में हुई है। उनकी जान-पहचान नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी से ठीक पहले शुरू हुई थी। ये एक सामान्य दोस्ती के रूप में शुरू हुई थी। डेटिंग की खबरों पर सिंगर ने कहा कि हम अभी भी एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि अगर लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन्हें अफवाहें ही रहने दूंगा। दिशा पाटनी से प्यार और फीलिंग्स को लेकर तलविंदर ने कहा कि मैं हर दिन प्यार में पड़ जाता हूं। मैं अभी प्यार में पड़ रहा हूं। हालांकि, इस दौरान तलविंदर ने दिशा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन इस बयान के समय ने दोनों के बीच रोमांटिक संबंध की अटकलों को और भी तेज कर दिया है। तलविंदर के इस बयान से दिशा और उनके रिलेशन की खबरों को और भी बल मिलता है।

बांधकर रखती है 'वध 2', अभिनय सबसे मजबूत पक्ष, क्लाइमैक्स में पासा पलटते हैं निर्देशक

संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा और शिल्पा शुक्ला जैसे दमदार अभिनेताओं से सजी यह फिल्म अभिनय के मामले में कहीं भी पीछे नहीं रहती। इसकी कहानी आपको पूरे समय बांधे रखती है। जसपाल सिंह संधू का कसा हुआ निर्देशन इसे और तगड़ा बनाता है। फिल्म में प्यार, हवस, बदला, क्रोध और चुप्पी सब कुछ है। कुल मिलाकर कैसी है ये फिल्म ? चलिए जान लेते हैंज फिल्म की शुरुआत 1994 से होती है जहां मंजू देवी (नीना गुप्ता) को डबल मर्डर के इल्जाम में 28 साल की सजा सुनाई जाती है। 28 साल से मंजू जिस जेल में बंद हैं उसी जेल का गार्ड शंभुनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) उससे प्यार करता है। शंभु जेल की सब्जियां चुराकर बाहर बेचता है और मंजू को जो भी मदद चाहिए होती है वो उसे उपलब्ध कराता है। इसी बीच प्रकाश सिंह (कुमुद मिश्रा) को जेल का नया अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। दूसरी तरफ जेल के एक बिगड़ैल कैदी केशव (अक्षय डोगरा) की, 23 वर्षीय महिला कैदी नैना (योगिता बिहानी) पर नजरें खराब हो जाती हैं। एक रात कुछ ऐसा होता है कि प्रकाश, केशव की पिटाई कर देता है जिसके बाद केशव जेल से गायब हो जाता है।

जांच बैठती है और पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर अतीत सिंह (अमित के सिंह) जेल आते हैं। आगे की पूरी कहानी केशव को ढूंढने और उसके साथ क्या हुआ? इस बारे बात करती है। फिल्म की शुरुआत में ही संजय और नीना के बीच एक दृश्य है। दोनों तारों से भरे आसमान के नीचे, एक-दूसरे को बिना देखे, जेल की दीवार के आर-पार एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

नए कलेक्ट्रेट भवन को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

मण्डला। जिले में विगत दिवस बुधवार 04/02/26 को अधिवक्ताओं ने विशाल रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की।अधिवक्ताओं ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण नगर सीमा में ही कराए जाने मांग की है।अधिवक्ता इस मुद्दे को लेकर बैठक आदि कर रहे हैं,लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नही लिया गया है।वर्तमान में जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कार्यालय के नवीन भवन का प्रस्तावित स्थल ग्राम चटुआमार में किया जा रहा है एवं शहर में पर्याप्त भूमिया स्थित होने के उपरांत भी शहर ग्राम चटुआमार में कलेक्ट्रेट भवन बनाये जाने से जनमानस में विरोध की स्थिति है चूंकि कलेक्ट्रेट भवन के साथ न्यायालय कलेक्टर जिला पेंशन अधिकारी ,जिला कोषालाय अधिकारी, जिला नजूल अधिकारी,लोकसेवा केन्द्र, रिकार्ड रूम,जिला खनिज शाखा,जिला खाद्य कलेक्टर के कार्यालय पूर्ण रूप से शहर से पृथक हाईवे के किनारे विस्थापित हो जाने से आम जनमानस को जानमाल के खतरा सहित अन्यत्र स्थान पर आने-जाने में भी काफी असुविधा होगी जिससे पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के ऊपर परिवहन एवं अन्य व्यय का बोझ बढेगा साथ ही आने जाने में अतिरिक्त समय व साधन की कमी आयेगी तथा अधिवक्तागण विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने में असमर्थ हो जायेंगे जिसका सीधा प्रभाव पक्षकारों को होने अतिरिक्त यात्रा व्यय का भुगतमान होगा साथ ही अधिवक्तागण को सिविल कोर्ट से पैरवी करने वाले न्याय पर पडेगा एवं सुलभ एवं सस्ते न्याय की परिपाटी में उक्त प्रस्ताव से न्याय की मंशा पर विपरीत प्रभाव पडेगा,चूंकि आप मण्डला के सांसद हैं एवं जिला मण्डला के निवासी हैं आज जनमानस,व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन उक्त प्रस्तावित निर्णय से काफी आहत हैं।जिला अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि नेहरू स्मारक स्थित पुराने पीडब्ल्यूडी की भूमि स्थित है,ज्ञानदीप स्कूल के सामने शासकीय भवनों एवं भूमियों का स्थान वर्तमान में आवंटित है,जिला खनिज,जिला आपूर्ति अधिकारी एवं महिला बाल विकास की पुरानी बिल्डिंग एवं भूमि को इस्तेमाल कर नवीन भवन का निर्माण किया जा सकता है।

वर्तमान में कलेक्टर कार्यालय को तोडकर उसी स्थान पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्मित कर उसका उपयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय के उद्यानिकी की भूमि पर वर्तमान में प्रकरण के लंबित काल में रोक संस्थित की गई है,उक्त प्रकरण के निराकरण उपरांत उक्त स्थल को प्रस्तावित किया जा सकता है महाराजपुर स्थित ठक्कर बापा परिसर के पास की भूमि पर भी विचार किया जा सकता है उक्त कंडिकावार सभी विकल्पों पर विचार कर शहर के आसान एवं पहुंच मार्ग पर जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी का कार्यालय का नवीन भवन प्रस्तावित किया जावे।अधिवक्ता समुदाय एवं अन्य जनमानस मिलकर जन आन्दोलन हेतु मजबूर होंगे।

दो दिन की देरी पड़ी भारी, 2 लाख के चेक बाउंस मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

न्यायालय ने कहा–विहित समयावधि में परिवाद प्रस्तुत न होने से धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध आकर्षित नहीं

भोपाल। दो लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त बलराम सहा को दोषमुक्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल की अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवादी संस्था द्वारा परिवाद पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता।

प्रकरण के अनुसार, भोपाल स्थित एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने अपने कर्मचारी बलराम सहा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विवाह एवं चिकित्सा कारणों से अग्रिम के रूप में 2,00,000 रुपये प्राप्त किए थे। बाद में राशि लौटाने के लिए अभियुक्त ने दिनांक 09 फरवरी 2016 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कृष्णापुरी शाखा, होशंगाबाद का चेक क्रमांक 297886 प्रदान किया। चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर लौट आया।

इसके पश्चात महाविद्यालय की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से 30 मार्च 2016 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया। आरोप था कि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अभियुक्त ने निर्धारित 15 दिनों की अवधि में भुगतान नहीं किया, जिस पर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने मुख्य आपत्ति यह उठाई कि परिवाद पत्र समय सीमा के बाहर दाखिल किया गया है। न्यायालय ने अभिलेखों और दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि विधिक नोटिस के पश्चात निर्धारित अवधि की गणना के अनुसार परिवाद 13 मई 2016 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जबकि इसे 16 मई 2016 को न्यायालय में दाखिल किया गया। इस प्रकार दो दिन का विलंब हुआ, जिसके संबंध में न तो कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया और न ही विलंब क्षमा का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के एडवोकेट संदीप मालवीय द्वारा उच्च न्यायालय की रुलिंग को पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विभिन्न न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 142 एनआई एक्ट के तहत निर्धारित समयावधि का पालन अनिवार्य है और उसके उल्लंघन पर लिया गया संज्ञान अवैध ठहराया जा सकता है। चूंकि परिवाद निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 का अपराध आकर्षित नहीं होता। अत: न्यायालय ने अभियुक्त बलराम सहा, निवासी रामकृष्ण नगर, होशंगाबाद, को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर दिया। साथ ही जमानत मुचलके निरस्त करने और धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह द्वारा खुले न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी 2026 को सुनाया गया। अभियुक्त बलराम शाह की ओर से पैरवी इटारसी निवासी एडवोकेट संदीप कुमार मालवीय ने की।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही

मुरैना। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर, सघन एवं प्रभावी संयुक्त कार्यवाही की गई। जिसमें चंबल राजघाट (भानपुर) और पिपरई में शुक्रवार, 6 फरवरी को वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 1,000 ट्रॉली अवैध चंबल रेत का विनिष्टिकरण किया गया। विनिष्टिकृत रेत का अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये बताया गया है। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल की प्रभावी तैनाती रही। जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह संयुक्त कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी। रेत विनिष्टिकरण की प्रक्रिया में 6 जेसीबी और 4 हाईड्रा का उपयोग किया गया। कार्यवाही के दौरान वनमंडलाधिकारी श्री हरिशचंद्र बघेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र डाबर, एसडीएम श्री बीएस कुशवाह, जिला खनिज अधिकारी श्री सुखदेव निर्मल, पुलिस लाइन के आरआई, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के एसडीओ सहित संबंधित राजस्व अमला उपस्थित रहा।

हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना में मृतक के वैध वारिस को 2 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

मुरैना। भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा (सोलेशियम) योजना, 1989 लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

केंद्र ने 24 आईएएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर इंपैनल्ड किया, मप्र के 2 आईएएस अधिकारी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने देश में विभिन्न कैडर के 24 आईएएसअधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी अथवा समकक्ष स्तर पर इंपैनल्ड किया है। इन अधिकारियों में मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारी शामिल है। यह दोनों अधिकारी 2010 बैच के हैं। इनके नाम गणेश शंकर मिश्रा और शनमुगा प्रिया मिश्रा है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्त होने के लिए 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा 24 अधिकारियों के पैनल में शामिल होने को मंजूरी दे दी। इन अधिकारियों में निधि श्रीवास्तव (एजीएमयूटी), साक्षी मित्तल (एजीएमयूटी), जितेंद्र यादव (एजीएमयूटी), अमरापली काटा (एपी), नारायण कोनवार (एएम), सुजीत कुमार (जीजे), हार्दिक सतीशचंद्र शाह (जीजे), एसएस नकुल (केएन), केबी शिवकुमार (केएन), गणेश शंकर मिश्रा (मप्र), शनमुगा प्रिया मिश्रा (मप्र), शैलेश नवल (महाराष्ट्र) आशुतोष सलिल (एमएच), उदय जी चौधरी (महाराष्ट्र), हरमीत सिंह पाहुजा (एमएन), कर्मा आर बोनपो (एसके), कपिल मीना (एसके), प्रवीण पी नायर (तमिलनाडु), रश्मी सिद्धार्थ जागड़े (तमिलनाडु), प्रीति मीना (टीजी), विकास सिंह (टीआर), महात्मे संदीप नामदेव (टीआर), के बालाजी (यूपी), विश्वनाथ (पश्चिम बंगाल) शामिल है।

सोना-चांदी का आयात होगा सस्ता, सरकार ने कर दी कम बेस इंपोर्ट प्राइस!

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने और चांदी की आयात पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बेस इंपोर्ट प्राइस (आधार आयात मूल्य) को कम कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में 1 नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी हैं कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया हैं जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहीं हैं। सरकार ने इस कदम से सोने-चांदी के आयतकों पर पड़ने वाला बोझ हल्का होगा।

जानिए क्या हो गया बेस प्राइस!

सीबीआईसी में सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस को उन 49 डॉलर प्रति 10 ग्राम घटाकर 1.518 डॉलर कर दिया हैं वहीं चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में 870 डॉलर प्रति किलोग्राम की कटौती की गई हैं जिससे यह 2,675 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गया हैं यह नई दरें उन सोने-चांदी पर लागू होगी जिनका आयात तय टेरीफ हेडिंग Tariff Headings के तहत किसी भी रूप में किया जाएगा। सरकार की इस ड्यूटी कटौती का फायदा हाई प्योरिटी गोल्ड बार और कॉइन साथ में सिल्वर बुलियन और मेडेलियन पर भी मिलेगा। हालांकि गहनों कीमती धातुओं से बनी अन्य वस्तुओं और पोस्ट, कूरियर या बैगेज के जरिए होने वाले आयात पर यह छूट लागू नहीं होगी।

इससे पहले कब बदला था बेस प्राइस?

चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस इससे पहले 27 जनवरी 2026 को बदल गया था जबकि सोने का भाव 22 जनवरी 2026 को आखिरी बार तय किया गया था। आमतौर पर सरकार हर पखवाड़े (2 सप्ताह) में कीमती धातुओं के बेस इंपोर्ट प्राइस को रिवाइज करती है। इस समय भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक हैं साथ ही भारत चांदी के लिए सबसे बड़ा बाजार हैं अपने यहां सोने के लगभग समूची मांग आयात से पूरी करनी होती हैं वहीं चांदी की 80त्न से अधिक जरूरत हैं यह भी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर करती हैं यह भी जान ले कि पिछले वर्ष भारत ने अपने कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग दसवां हिस्सा सोने-चांदी के आयात पर खर्च किया था। अनुमान हैं कि 2026 तक या इंपोर्ट बिल और बढ़ सकता है क्योंकि दोनों धातुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं!

अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो कभी गांव सड़क से नही जुड़ पाते

वी बी- जी राम जी को लेकर भाजपा का छिंदवाड़ा जनपद का हुआ सम्मेलन

छिंदवाड़ा। वी.बी.-जी राम जी के छिंदवाड़ा जनपद के संयोजक एवं अन्त्योदय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संतोष पटेल ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजय सक्सेना, बी.बी. जी रामजी के जिला संयोजक एवं किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, सहसंयोजक शिव पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमाकांत पटेल, ओम पटेल, दिनेशकांत मालवी, मंडल संयोजक गोलू सुशील चौधरी, रूपसिंग पटेल, संतोष चंद्रवंशी, अम्बिका गेंदसिंह बानखेड़े, घनानन्द कमलनाथ पटेल की मुख्य उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में जी राम जी बिल को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा बी.बी. जी राम जी विधेयक 2025 को पारित किया गया जिससे ग्रामीण आजीविका मिशन को गति मिलेगी जिससे भ्रष्टाचार पर रोक रहेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अब 100 दिन के रोजगार से बढ़कर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अब साप्ताहिक राशि सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान की जाएगी। गांव स्तरीय योजनाएं पहले तैयारी की जाएगी फिर ब्लाक, जिला एवं राज्यस्तर, राष्ट्रीय स्तर पर डिजीटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति से संयोजित होगी साथ ही बिल को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन में जी राम जी के जिला संयोजक संजय पटेल ने कहा कि यह बिल विकसित भारत की ओर एक मील का पत्थर साबित होगा तथा गांधी के सपनों को साकार करने में इस बिल की महती भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के समग्र कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए है अगर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तब भारत के 6 लाख गांव कभी सड़क से जुड़ नहीं पाते तथा किसान क्रेडिट कार्ड भी अस्तित्व में नहीं आता तथा सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आता

इस अवसर पर महामंत्री प्रहलाद पटेल, विजय मसराम, श्रीमती संगीता परतेती, श्रीमती फुलेश सूर्यवंशी, शिशिर चौरिया, सुधाकर लियांगत, झनकलाल पटेल, श्रीमती स्वर्णमाला, सुनील डेहरिया, विजय सूर्यवंशी, मनोहर पटेल, जय ठाकुर, रामादीन दुबे, धर्मेन्द पाल सहित सरपंच, उपसरपंच, जनपद सदस्य उपस्थित रहे। सम्मेलन में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रभारी नियुक्त किए गए।

मध्यप्रदेश के एयरपोर्ट होंगे 17 बड़े शहरों से कनेक्ट, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सौगात

भोपाल। जल्द ही मध्यप्रदेश से सिंगापुर, दुबई, शारजहां, दोहा, अबुधाबी, जेद्दाह, कुआलालम्पुर सहित आठ देशों के लिए वायु सेवा शुरु की जाएगी. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार विमानन कंपनियों को आर्थिक अनुदान भी उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही प्रदेश से अन्य राज्यों के बड़े शहरों के बीच सत्रह घरेलू वायुसेवाएं भी शुरू की जाएंगी. नई विमानन नीति के तहत विमानन विभाग ने मध्य प्रदेश से 17 घरेलू और 8 विदेशों के लिए आर्थिक अनुदान वाली वायुसेवा शुरु करने के लिए विमानन कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए है. ये प्रस्ताव 25 फरवरी तक बुलाए गए है. पहले जो प्रस्ताव बुलाए थे. उसमें रीवा के लिए वायु सेवा शुरू की गई थी.दूसरे प्रस्ताव में मध्यप्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, इंदौर, सतना, खजुराहो, एवं दतिया से अन्य राज्यों में रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा, भुवनेश्वर, रांची, अमृतसर एवं चंडीगढ़ हेतु घरेलू वायुसेवाएं शुरू करने के लिए निजी विमानन कंपनियों से प्रस्ताव बुलाए गए हैं. इन एयरलाइंस कंपनियों को पचास सीटर या इससे अधिक सीट की घरेलू वायुसेवा प्रारंभ करने पर 750 किलोमीटर तक के लिए एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम साढ़े सात लाख रुपए और 750 किलोमीटर से अधिक की वायुसेवाएं उपलब्ध कराने पर एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर प्रति राउंड अधिकतम दस लाख रुपए तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा.अंतरराष्ट्रीय उड़ाने संचालित करने पर 180 सीटर वायु सेवा शुरु करने के लिए एक हजार किलोमीटर से अधिक दूरी की उड़ान पर एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर प्रति राउंड अधिकतम पंद्रह लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार विमानन कंपनियों को उपलब्ध कराएगी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए एक नया विमान राज्य सरकार के विमानन बेड़े में इस साल मई तक आ जाएगा. हेलीकॉप्टर अगले साल जनवरी बेड़े में शामिल हो जाएगा. कंपनियां 11 विभाग को प्रस्ताव भेज सकेंगे. उन्हें 12 फरवरी को डायरेक्ट खोला जाएगा.

150 से अधिक मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रस्तुत की विज्ञान, एआई और भारतीय ज्ञान परंपरा की झलक

टी.आर.एम स्कूल पुरानी इटारसी में ज्ञान की ज्योति 'उद्भास' से आलोकित हुआ परिसर

इटारसी। टी.आर.एम स्कूल, पुरानी इटारसी में आज विद्यार्थियों द्वारा आयोजित ज्ञान प्रदर्शनी 'उद्भास' ने शिक्षा और रचनात्मकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक शिक्षा सहित 11 विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी ने न केवल अभिभावकों और अतिथियों को प्रभावित किया, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और नवाचार क्षमता की भी शानदार झलक दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विकास सलाहकार समिति, नर्मदापुरम के सदस्य श्री सत्यम अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। श्री अग्रवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी से संवाद स्थापित किया और उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडलों की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्य को समझा। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत, समर्पण और लगन की भूरी-भूरी प्रशंसा की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने प्रदर्शनी के नाम 'उद्भास' का अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 'उद्भास' का आशय है–प्रकाशित होना या ज्ञान के माध्यम से जीवन को आलोकित करना। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में विभिन्न विषयों से प्राप्त सीख ही उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद और नैतिक मूल्यों का संतुलन ही व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार है।

नन्हे विद्यार्थियों ने जीता सबका दिल

प्रदर्शनी का सबसे आकर्षक और भावनात्मक क्षण वह रहा जब कक्षा केजी के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल प्रस्तुत किए। छोटे-छोटे बच्चों की स्पष्ट अभिव्यक्ति और विषय की समझ ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। उनके प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती।

नवाचार और रचनात्मकता की झलक

प्रदर्शनी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े आधुनिक विषयों के साथ-साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और नैतिक शिक्षा जैसे मूल्यों पर आधारित मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित परियोजनाओं ने डिजिटल युग की समझ को दर्शाया, वहीं भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित मॉडलों ने छात्रों की जड़ों से जुड़ाव को प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों ने अपने-अपने विषयों को न केवल सैद्धांतिक रूप से समझा, बल्कि उसे व्यवहारिक मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत कर सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बना दिया।

शिक्षिकाओं के योगदान की सराहना

विद्यालय की प्राचार्या सुश्री रश्मा भाटिया ने विद्यार्थियों को इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन, परिश्रम और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना इस भव्य आयोजन की सफलता संभव नहीं थी।

शिक्षा और संस्कार का समन्वय बना 'उद्भास' की पहचान

'उद्भास' केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर निहित ज्ञान, जिज्ञासा और सृजनात्मकता का उत्सव बनकर सामने आया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब शिक्षा में नवाचार और संस्कार का समन्वय होता है, तब ज्ञान वास्तव में जीवन को आलोकित करता है।

स्वामी प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक विनोद सिंह तोमर द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन-1 भोपाल (म.प्र) से मुद्रित एवं 87, पुट्ठामिट गेट के सामने, छोला रोड, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से प्रकाशित।
संपादक : विनोद सिंह तोमर मो. 7067515898, स्थानीय- संपादक संजय सक्सेना RNI NO. MPHIN/2015/61965 (सभी विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य होगा।)